वर्ष 13 • अंक 23 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शनिवार 14 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट

नीरज गोविल पृष्ठ 2

विस्तार की रफ्तार धीमी रखेगी मैरियट

डॉलर रु. 73.90 ▼ 30 पैसे | यूरो रु. 82.60 ▼ 70 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 41849 ▼ 1351 रुपये | सेंसेक्स 34103.50 ▲ 1325.30 | निफ्टी 9955.20 ▲ 365.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 9897.70 ▼ 57.50 | ब्रेंट क्रूड 33.90 डॉलर ▲ 02.70 डॉलर

तेज गिरावट के बाद जोरदार वापसी

- प्रोत्साहन की उम्मीद में बाजार में सुधार, दिन के निचले स्तर से 16 फीसदी चढ़ा निफ्टी
- निफ्टी के लोअर सर्किट छूने के बाद 45 मिनट तक रोकना पड़ा कारोबार
- दिन के निचले स्तर से सेंसेक्स ने की 5,000 अंक की वापसी

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 13 मार्च

भारतीय शेयर बाजार में आज बहुत उतार-चढ़ाव दिखा। कोरोनावायरस की चिंता से हो रही चौतरफा बिकवाली के बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रोत्साहन उपायों की घोषणा करने से बाजार ने अपने दिन के निचले स्तर से करीब 16 फीसदी बढ़त हासिल की। सुबह शुरुआती कारोबार में ही निफ्टी 10 फीसदी टूट गया, जिसकी वजह से 16 साल में पहली बार एक्सचेंजों पर कारोबार रोकना पड़ा। उधर, अमेरिकी वायदा और एशियाई बाजारों में अप्रत्याशित सुधार देखा गया, जिसका असर निवेशकों की धारणा पर पड़ा। 8,555 अंक के स्तर तक लुढ़कने के बाद कारोबार की समाप्ति पर निफ्टी 365 अंक चढ़कर 9,955 पर बंद हुआ। इसी तरह सेंसेक्स 29,389 के स्तर तक फिसल गया था लेकिन इसने 4,700 अंक के साथ अच्छी वापसी की और कारोबार की समाप्ति पर 34,103 पर बंद हुआ।

घरेलू बाजार के साथ ही एशियाई बाजारों में शुरुआती गिरावट की मुख्य वजह डाऊ जोंस सूचकांक के 10 फीसदी लुढ़कने की वजह से आई थी। दिन भर शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव बना रहा और कई शेयर तो 30 फीसदी के दायरे में घूमते रहे। इससे एक दिन पहले निफ्टी 33 माह के निचले स्तर पर बंद हुआ था और घरेलू बाजार मंदड़ियों की गिरफ्त में पहुंच गया था।

बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए एशियाई केंद्रीय बैंकों ने कई उपायों की घोषणा कीं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने रिवर्स अनुपात को कम कर अर्थव्यवस्था में 79 अरब डॉलर डालने का निर्णय किया। इसी तरह बैंक ऑफ जापान ने 20.8 अरब डॉलर की तरलता मुहैया कराने की बात कही है। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ कोरिया ने अपनी मुद्रा में उतार-चढ़ाव को काबू में करने के लिए कदम उठाए। उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका भी आर्थिक नरमी को दूर करने के लिए कोई प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकता है। इस बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने का वादा किया है। 2008 के संकट के समय भी बॉन्ड खरीद कार्यक्रम के जरिये अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया था।

जियोजित फाइनैंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बाजार में तेज वापसी मुख्य रूप से प्रोत्साहन उपायों की उम्मीद में आई है।

डाल्टन कैपिटल इंडिया में निदेशक यूआर भट्ट ने कहा, 'एक और तेज गिरावट के बाद कुछ ने मार्जिन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए घबराहट में बिकवाली की। लेकिन सुबह की गिरावट के बाद कई शेयरों ने अच्छी वापसी की।'

विश्लेषकों ने कहा कि बाजार में गिगरावट के बाद सुधार में प्रोत्साहनों के अलावा शॉर्ट कवरिंग का भी योगदान रहा है। बाजार के भागीदारों का कहना है कि बाजार की चिंता अभी दूर नहीं हुई है क्योंकि कोविड-19 से जुड़े मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों की ओर से भी बिकवाली बनी हुई है।

विदेशी निवेशकों ने आज 6,000 करोड़ रुपये के शेयर बेचे और पिछले 14 दिन में 43,000 करोड़ रुपये की बिकवाली कर चुके हैं। (शेष पृष्ठ 3 पर)

9,955.2

9,590.2

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सरकार भी बाजार की गतिविधियों पर नजर रख रही है

निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री

इस सप्ताह निफ्टी में 1034 (9.40 फीसदी) अंक की गिरावट

पिछले चार सत्रों में निवेशकों को 15 लाख करोड़ रुपये का चूना

इससे पहले 22 जनवरी, 2008 को सर्किट के बाद थमा था कारोबार

8,555.2

निफ्टी की दमदार वापसी की पांच मिसाल

तारीख	बंद	गिरावट * (%)	वापसी # (%)	अंतिम आंकड़े (%)
13/03/20	9,955.2	-10.8	16.4	3.8
27/10/08	2,524.2	-12.8	12.0	-2.3
22/01/08	4,899.3	-14.6	10.1	-5.9
17/10/07	5,559.3	-9.9	8.9	-1.9
17/05/04	1,388.8	-18.3	7.5	-12.2

*पिछले बंद भाव से निचले स्तर तक, #शुक्रवार के निचले स्तर से बंद भाव

इनका प्रदर्शन रहा बेहतर

13 मार्च तक

कंपनी	निचला	बंद भाव	%बदलाव
इंडसइंड बैंक	551.1	803.8	45.8
बीपीसीएल	275.5	376.1	36.5
ओएनजीसी	50.0	65.9	31.8
एसबीआई	184.7	242.0	31.1
गेल इंडिया	65.0	84.6	30.1

स्रोतः ब्लूमबर्ग/एक्सचेंज | संकलनः बीएस रिसर्च ब्यूरो

येस बैंक को मिलेंगे 11,000 करोड़ रुपये

सोमेश झा और सुब्रत पांडा
नई दिल्ली/मुंबई, 13 मार्च

संकट से जूझ रहे येस बैंक को बचाने के लिए निजी क्षेत्र के अन्य बैंकों ने इसमें निवेश करने का फैसला किया है। इनमें एफडीएफसी, कोटक महिन्द्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और ऐक्सिस बैंक शामिल हैं। साथ ही सरकार ने भी येस बैंक को पटरी पर लाने की योजना को आज मंजूरी दे दी।

इस योजना के मुताबिक विभिन्न वित्तीय संस्थान येस बैंक में 11,350 करोड़ रुपये इक्विटी निवेश करेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक एक-एक हजार करोड़ रुपये, ऐक्सिस बैंक 600 करोड़ रुपये और कोटक महिन्द्रा बैंक 500 करोड़ रुपये येस बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश करेंगे। इन बैंकों के बोर्ड ने शुक्रवार को यह फैसला किया। भारतीय स्टेट बैंक पहले ही 7,250 करोड़ रुपये निवेश करने का वादा कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) येस बैंक में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि निवेश करेगा। उसकी पहले से ही बैंक में 8.06 फीसदी हिस्सेदारी है। सभी निवेशक येस बैंक में 10 रुपये प्रति शेयर के भाव से हिस्सेदारी खरीद रहे हैं।

- 18 मार्च को हट जाएगी निकासी की सीमा
- 25 मार्च तक गठित हो जाएगा नया बोर्ड

इस तरह एचडीएफसी लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक येस बैंक में 5 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी लेंगे। आईसीआईसीआई और एसबीआई को आरबीआई अहम बैंक मानता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे बैंक जो बहुत बड़े हैं और जिनके डूबने की आशंका नहीं है। एचडीएफसी लिमिटेड की दो अन्य बैंकों एचडीएफसी बैंक और बंधन बैंक में हिस्सेदारी है। एचडीएफसी बैंक भी अहम बैंकों की श्रेणी में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में येस बैंक के पुनर्गठन की योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इस बैंक की अधिकृत पूंजी को 1,100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6,200 करोड़ रुपये करने का फैसला किया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तत्काल और भविष्य की पूंजी जरूरतों को समायोजित करने के लिए यह फैसला किया गया है। एसबीआई येस बैंक में 49 फीसदी तक इक्विटी हासिल करने के लिए निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना और बैंक एवं वित्तीय प्रणाली में स्थायित्व सुनिश्चित करना है। येस बैंक में इन बैंकों द्वारा किए जाने वाले निवेश पर तीन साल की लॉक-इन अवधि होगी। (शेष पृष्ठ 3 पर)

एक नज़र

एयर इंडिया के लिए बोली अब 30 अप्रैल तक

एयर इंडिया खरीदने की इच्छुक कंपनियों के लिए सरकार ने बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख 17 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। इस संबंध में शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की गई। एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बनाए गए मंत्रिसमूह ने अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय किया। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और संभावित खरीदारों के अनुरोध पर गौर करते हुए अंतिम तारीख बढ़ाने का निर्णय किया गया है। पृष्ठ 4

मास्क, हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु घोषित

सरकार ने कोरोनावायरस के कहर को ध्यान में रखते हुए मास्क (एन 95 सहित) और हैंड सैनिटाइजर को 'आवश्यक वस्तु' घोषित कर दिया है। इस वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने के बाद इन दोनों वस्तुओं की कालाबाजारी शुरू हो गई है। जून अंत तक इन दोनों वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाएगा। सरकार ने शुक्रवार को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इन वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की।

विवाद से विश्वास विधेयक को संसद की मंजूरी

संसद ने शुक्रवार को उस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके तहत करदाताओं को अपने कर विवादों के हल के लिए केवल विवादित कर राशि का भुगतान करना होगा और उन्हें ब्याज एवं जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी, लेकिन भुगतान 31 मार्च तक करना होगा। राज्यसभा ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 को संक्षिप्त चर्चा के बाद लौटा दिया क्योंकि यह धन विधेयक है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि योजना की समाप्ति की तिथि सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी और इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। पृष्ठ 4

पिछले 7 महीने में पहली बार बढ़ा निर्यात

भारत से होने वाला निर्यात फरवरी में 2.91 प्रतिशत बढ़कर 27.65 अरब डॉलर हो गया। शुक्रवार को वाणिज्य मंत्रालय देश के आयात एवं निर्यात का आंकड़ा जारी किया। पिछले सात महीनों में पहली बार देश से होने वाले निर्यात में तेजी दिखी है। हालांकि निर्यात के साथ देश का आयात भी बढ़ा। आलोच्य महीने में आयात 2.48 प्रतिशत बढ़कर 37.5 अरब डॉलर हो गया। इस तरह, व्यापार घाटा 9.85 अरब डॉलर हो गया, जो फरवरी 2019 में 9.72 अरब डॉलर रहा था। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-फरवरी अवधि में निर्यात 1.5 प्रतिशत बढ़कर 292.91 अरब डॉलर हो गया। इसी अवधि के दौरान आयात 7.30 प्रतिशत बढ़कर 436 अरब डॉलर रह गया। पृष्ठ 4

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 21 फीसदी करने को मंजूरी दे दी। इससे सरकारी खजाने पर 14,595 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 21 फीसदी करने को मंजूरी दे दी।

कोरोना ने थामी बेंगलूरु की रफ्तार

समरीन अहमद और नेहा अलावधी
बेंगलूरु/नई दिल्ली, 13 मार्च

विश्वव्यापी महामारी घोषित किए गए कोरोनावायरस ने भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलूरु की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं। शहर में अधिकांश शीर्ष कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से काम करने को कह रही हैं। कर्नाटक सरकार ने सभी मॉल, सिनेमाघर और भीड़भाड़ वाले इलाकों को शनिवार से बंद करने का आदेश दिया है।

अमेरिका की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने गुरुवार को उसके एक कर्मचारी में कोरोनावायरस के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद शहर में अपने कार्यालय को बंद कर दिया और एहतियात के तौर पर अपने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि बेंगलूरु कार्यालय में उसके एक कर्मचारी में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोनावायरस के लक्षण दिखने से पहले यह कर्मचारी कुछ समय के लिए कंपनी के कार्यालय में रहा था। इसके बाद से उसने खुद को अलग कर दिया था। उसके संपर्क में आए अन्य कर्मचारियों ने भी खुद को अलग कर लिया है और वे अपने स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं।

हालांकि गुरुग्राम में गूगल के कर्मचारियों ने कहा कि वहां सामान्य कामकाज चल रहा है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है और कर्मचारियों को संक्रमण से दूर रखने के लिए साफ-सफाई के सारे उपाय किए जा रहे हैं।

बेंगलूरु में डेल और माइंडट्री के बाद गूगल तीसरी ऐसी प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसके कर्मचारी में कोरोनावायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। (शेष पृष्ठ 12 पर)

- एक सप्ताह के लिए थम जाएगी रफ्तार
- शनिवार से मॉल, सिनेमाघर बंद करने का आदेश
- गूगल के कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि
- कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह

कोरोना का डर... आईपीएल 15 अप्रैल तक के लिए टला

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 13 मार्च

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। सूत्रों के अनुसार इसके बाद बीसीसीआई देश में कोरोनावायरस के संक्रमण के मद्देनजर आगे कोई निर्णय लेगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली कुछ दिनों पहले तक कहते रहे थे कि आईपीएल का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। सूत्रों की मानें तो बीसीसीआई इस टूर्नामेंट की आयोजन तिथि 29 मार्च से थोड़ा खिसका कर इसे किसी भी हालत में आयोजित करने की पूरी जुगत लगा रहा है। इस वर्ष के आईपीएल संस्करण में 11,000 करोड़ रुपये दांव पर लगे हैं। टूर्नामेंट अगर रद्द होता है तो प्रायोजकों के साथ ही टीमों और खिलाड़ियों के लिए भी इसके गंभीर वित्तीय परिणाम होंगे। अमेरिका की दिग्गज मीडिया कंपनी डिज्नी ने आईपीएल मैचों के प्रसारण और डिजिटल अधिकार खरीदे हैं।

सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई के लिए टूर्नामेंट 17 मई से आगे खींचना आसान नहीं होगा क्योंकि आगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित होनी हैं और विदेशी खिलाड़ी भी उपलब्ध नहीं रहेंगे। सीमित समय में टूर्नामेंट निपटाने के लिए हरेक दिन दो मैच आयोजित करने होंगे। अमूमन शनिवार और रविवार को दो-दो मैच होते रहे हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि कोरोनावायरस के संक्रमण में कमी नहीं आई तो मैच खाली स्टेडियम में कराने होंगे। इस बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही एकदिवसीय श्रृंखला के बाकी दो मैच रद्द कर दिए गए हैं। सरकार ने मौजूदा हालात से निपटने के लिए विदेशी यात्रियों के 15 अप्रैल तक भारत नहीं आने देने का फरमान दिया है। इससे समस्याएं और बढ़ सकती हैं क्योंकि जो विदेशी खिलाड़ी भारत आना भी चाहते हैं, उनके लिए भी भारत का वीजा लेना आसान नहीं होगा। हालांकि अगले दो हफ्तों में हालात सुधरे तो यह सभी लिहाज से आईपीएल के लिए शुभ साबित हो सकता है।

- इस वर्ष आईपीएल पर **11,000** करोड़ रुपये लगे हैं दांव पर
- डिज्नी ने प्रसारण अधिकार के लिए दिए हैं **3,270** करोड़ रुपये
- खाली स्टेडियम में मैच होने से टीमों को हो सकता है **80** से **100** करोड़ रुपये का नुकसान
- मैच नहीं होने पर खिलाड़ियों को फीस के रूप में **700** करोड़ रुपये का हो सकता है नुकसान

आईपीएल के शीर्ष प्रबंधन और बीसीसीआई के बीच शुक्रवार को मुंबई में हुई बैठक के बाद एक बयान में कहा गया, 'बीसीसीआई ने एहतियात के तौरपर 15 अप्रैल 2020 तक आईपीएल टूर्नामेंट निलंबित करने का निर्णय लिया है।' आईपीएल का शीर्ष प्रबंधन शनिवार को आठों टीमों को अपने निर्णय के बारे में और विस्तार से जानकारी देगा।

आईपीएल 15 अप्रैल तक टलने के निर्णय से पहले दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि मौजूदा परिस्थितियों में वह आईपीएल सहित किसी खेल के आयोजन की अनुमति नहीं देंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि राज्य सरकार केवल खाली स्टेडियमों में ही मैच खेलने की अनुमति देगी। समझा जा रहा है कि बीसीसीआई ने इन बयानों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।

टूर्नामेंट रद्द होने पर सबसे अधिक नुकसान बीसीसीआई को उठाना होगा। इस बार मैचों के प्रसारण एवं डिजिटल अधिकार बेचने से बीसीसीआई को 4,200 करोड़ रुपये राजस्व मिलने की उम्मीद है। मैच अगर खाली स्टेडियमों में होते हैं तो इससे बीसीसीआई और आईपीएल टीमों को नुकसान सीमित रहेगा, क्योंकि उन्हें टिकट की बिक्री से अधिक रकम नहीं मिलती है। डिज्नी आईपीएल की दूसरी बड़ी भागीदार है, जिसने डिजिटल एवं प्रसारण अधिकार के लिा 3,270 करोड़ रुपये चुकता किए हैं।

मैच रद्द होने पर इसे 3,000 करोड़ रुपये से अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि खाली स्टेडियम में मैच होने से इसे नुकसान नहीं होगा। आईपीएल के कुल दर्शकों में करीब 1 प्रतिशत ही स्टेडियमों में मैच देखते हैं और मैच खाली स्टेडियम में होने से वे भी टेलीविजन या हॉटस्टार (ओटीटी प्लेटफॉर्म) पर मैच देखेंगे।

संक्षेप में

विदेशी मुद्रा भंडार 5.69 अरब डॉलर बढ़ा

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 मार्च को समाप्त सप्ताह में 5.69 अरब डॉलर बढ़कर 487.23 अरब डॉलर के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। विदेशीमुद्रा आस्तियों में वृद्धि से सकल भंडार बढ़ा है। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.419 अरब डॉलर बढ़कर 481.540 अरब डॉलर पर पहुंचा था। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा यानी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 5.311 अरब डॉलर बढ़कर 451.135 अरब डॉलर पर पहुंच गईं। *भाषा*

टाटा स्टील को रकम जुटाने की मंजूरी

टाटा स्टील को उसके निदेशकों की समिति से 670 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति मिल गई है। कंपनी गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर यह रकम जुटाएगी। स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि निदेशकों की समिति कंपनी को असुरक्षित, भुनाने योग्य, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर 670 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए कंपनी निजी नियोजन के आधार पर चुनिंदा निवेशकों को 10,00,000 रुपये अंकित मूल्य के डिबेंचर जारी करेगी। कंपनी का इन डिबेंचरों को बीएसई के थोक बॉन्ड बाजार में सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव है। *भाषा*

फेडरल बैंक के पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध

फेडरल बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसकी संपत्ति की गुणवत्ता अच्छी है और उसके पास नियामकीय आवश्यकता की तुलना में पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। बैंक ने एक बयान में कहा, फेडरल बैंक के पास उपलब्ध पर्याप्त पूंजी का अनुपात वित्त वर्ष 2018-19 में 14.14 फीसदी रहा, जबकि नियामकीय जरूरत 9 फीसदी है। उसने कहा, बैंक के पास उपलब्ध पर्याप्त पूंजी का अनुपात 31 दिसंबर 2019 तक 13.64 फीसदी था, जिसमें टियर-1 पूंजी 12.62 फीसदी है। इससे पूंजी के मोर्चे पर बैंक की अच्छी स्थिति का पता चलता है। बैंक का एनपीए भी 2.92 फीसदी है जबकि बैंकिंग क्षेत्र का औसत एनपीए 9.1 फीसदी है। इससे पहले कुछ अन्य बैंक भी इस तरह की सफाई दे चुके हैं। *भाषा*

थर्मेक्स देगी 350 फीसदी अंतरिम लाभांश

इंजीनियरिंग फर्म थर्मेक्स ने शुक्रवार को साल 2019-20 के लिए 7 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश का ऐलान किया, जो 2 रुपये मूल्य वाले शेयरों पर दिया जाएगा। कंपनी ने बीएसई को भेजी सूचना में कहा, 13 मार्च को हुई निदेशक मंडल की बैठक में 7 रुपये प्रति शेयर यानी 350 फीसदी अंतरिम लाभांश देने की मंजूरी दी गई। बयान के मुताबिक, जिन शेयरधारकों के पास 23 मार्च 2020 को कंपनी के शेयर होंगे, वे लाभांश के हकदार होंगे। *एजेंसियां*

यात्री वाहनों की बिक्री घटी

फरवरी में यात्री वाहनों की बिक्री 7.6 फीसदी घटी, लदान 19.08 फीसदी घटा

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 13 मार्च

घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री फरवरी 2020 में करीब 7.61 फीसदी घटकर 2,51,516 वाहन रह गई। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सायम के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। एक साल पहले यानी फरवरी 2019 में 2,72,243 वाहनों की बिक्री हुई थी।

यात्री कार की बिक्री फरवरी में 8.77 फीसदी घटकर 1,56,245 वाहन रह गई जो पिछले साल फरवरी में 1,71,307 वाहन रही थी। इन वाहनों की थोक बिक्री में गिरावट की मुख्य वजह आर्थिक मंदी और बीएस4 वाहनों का कम उत्पादन रही।

फरवरी में दोपहिया वाहनों की बिक्री 19.82 फीसदी घटकर 12,94,791 वाहन रह गई जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 16,14,941 वाहन रहा था। सायम ने बताया कि वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री फरवरी 2020 में 32.9 फीसदी घटकर 58,670 वाहन रह गई जबकि पिछले साल फरवरी में 87,436 वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री हुई थी। सायम के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के वाहनों की बिक्री 19.08 फीसदी घटकर 16,46,332 वाहन रह गई जबकि जरवरी 2019 में 20,34,597 वाहनों की बिक्री हुई थी।

सायम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि उत्पादन में भारी गिरावट और फरवरी 2020 में सभी श्रेणियों की थोक बिक्री में गिरावट के कारण वाहन उद्योग लगातार चुनौतियों से जूझ रहा है। सायम के अध्यक्ष राजन वढ़ेरा ने कहा कि थोक बिक्री में गिरावट मुख्य तौर पर आर्थिक मंदी और बीएस4 वाहनों के कम उत्पादन के कारण आई।

हालांकि वाहनों की पंजीकरण संख्या में कुछ वृद्धि दिख सकती है क्योंकि ग्राहक अंतिम समय में बीएस4 वाहनों की खरीदारी कर सकते हैं। वाहन डीलरों के संठगन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) ने गुरुवार को वाहनों की बिक्री के खुदरा आंकड़े जारी किए। उन आंकड़ों से पता चलता है कि करीब 11 महीने के बाद खुदरा वाहन बिक्री में सुधार हुआ है। हालांकि यात्री वाहनों की बिक्री फरवरी 2020 में 2.6 फीसदी बढ़कर 17,11,711 वाहन हो गई जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 16,68,268 वाहनों का रहा था।

वढ़ेरा ने कहा, 'चीन से आपूर्ति शृंखला में उथल-पुथल भी चिंता का विषय है। इससे आगे चलकर कंपनियों की उत्पादन योजना प्रभावित हो सकती है।' कार विनिर्माताओं का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बिक्री में वृद्धि शहरी बाजारों के मुकाबले अधिक रही क्योंकि ग्रामीण बाजार की धारणा फिलहाल अच्छी है। अच्छे मॉनसून, रबी और खरीफ फसलों के कारण ग्रामीण आय बढ़ी है जिससे खरीदारों की धारणा सकारात्मक बनी है।

बिक्री रफ्तार सुस्त

- यात्री कार की बिक्री फरवरी में 8.77 फीसदी घटकर 1,56,245 वाहन रह गई
- दोपहिया वाहनों की बिक्री 19.82 फीसदी घटकर 12,94,791 वाहन रह गई
- वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री फरवरी 2020 में 32.9 फीसदी घटकर 58,670 वाहन रह गई
- विभिन्न श्रेणियों के वाहनों की बिक्री 19.08 फीसदी घटकर 16,46,332 वाहन रह गई

निर्यात

हालांकि घरेलू बिक्री कमजोर बनी हुई है लेकिन निर्यात में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। फरवरी में वाहनों का निर्यात 11.05 फीसदी बढ़कर 4,15,329 वाहन हो गया। इसमें यात्री वाहनों का योगदान सबसे अधिक रहा। महीने के दौरान यात्री वाहनों के निर्यात में 8.86 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई जबकि दोपहिया वाहनों के निर्यात में 15.64 फीसदी की वृद्धि हुई। वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात 19.60 फीसदी घट गया जबकि यात्री कार के निर्यात में 4.5 फीसदी की कमी आई।

उत्पादन

जहां तक उत्पादन का सवाल है तो फरवरी 2020 में सभी श्रेणियों के उत्पादन में 18.14 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान 20,25,931 वाहनों का उत्पादन हुआ जबकि फरवरी 2019 में यह आंकड़ा 24,75,018 वाहनों का रहा था।

बीएस4 दोपहिया वाहन अभी भी बिना बिके मौजूद

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 13 मार्च

नए उत्सर्जन मानदंड को लागू करने के लिए अब महज दो सप्ताह का समय बचा है लेकिन देश में दोपहिया वाहनों के डीलरों के पास अभी भी बीएस4 वाहनों की करीब 3,800 करोड़ रुपये की इन्वेंटरी बची है। वाहन डीलरों का संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) का कहना है कि तमाम दोपहिया वाहन डीलरों के पास बीएस4 वाहनों की काफी इन्वेंटरी बची है।

फाडा का कहना है कि मूल उपकरण विनिर्माताओं से पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण उसके सदस्यों को बीएस4 वाहनों को खपाने में परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि 31 मार्च के बाद बीएस4 उत्सर्जन मानदंड वाले वाहनों की बिक्री भारत में नहीं होगी क्योंकि देश में अब केवल नए उत्सर्जन मानदंड बीएस6 वाले वाहनों की बिक्री की जाएगी।

फाडा का कहना है कि डीलरों के पास बीएस4 उत्सर्जन मानदंड वाले करीब 7 लाख दोपहिया वाहनों का स्टॉक बचा है जिनका कुल मूल्य करीब 3,850 करोड़ रुपये है। उनका कहना है कि बीएस4 उत्सर्जन मानदंड वाले दोपहिया वाहनों की इन्वेंटरी चिंताजनक है जबकि पुराने उत्सर्जन मानदंड वाले यात्री एवं वाणिज्यिक वाहनों की इन्वेंटरी लगभग नगण्य है। फाडा के अध्यक्ष आशिष हर्षराज काले ने कहा कि बीएस4 दोपहिया वाहनों की इन्वेंटरी डीलरों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय बीएस4 वाहनों की बिक्री के लिए समय सीमा में विस्तार के लिए हमारे आवेदन पर विचार नहीं कर रहा है। ऐसे में फाडा मूल उपकरण विनिर्माताओं से आग्रह करता है कि वे बीएस4 वाहनों को पूरी तरह खपाने में डीलरों की मदद करें। फाडा के सर्वेक्षण से पता चला है कि बड़ी तादाद में दोपहिया डीलर बीएस4 वाहनों की इन्वेंटरी को पूरी तरह खपाने में असमर्थ हैं और उन्होंने स्टॉक को पूरी तरह खपाने के लिए ओईएम से मदद मांगी है।'

काले ने कहा कि यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में कुल मिलाकर इन्वेंटरी उचित स्तर पर है लेकिन कम लोकप्रिय मॉडलों को खपाने के लिए डीलरों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्च के अंत तक इन वाहनों का बाजार में खपाने के लिए डीलरों को मूल उपकरण विनिर्माताओं से मदद की दरकार है। फाडा अनबिके बीएस4 वाहनों को लौटाने की वकालत पहले ही कर चुका है।

स्पाइसजेट के लिए कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी बनाएगी जीएमआर

बीएस संवाददाता
हैदराबाद, 13 मार्च

जीएमआर हैदराबाद इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड (जीएसएएसएल) विमानन कंपनी स्पाइसजेट के लिए गोदाम, वितरण एवं व्यापार गतिविधियों के लिए एक प्रतिष्ठान का निर्माण करेगी। इसका निर्माण शहर में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन में किया जाएगा जिसे आमतौर पर जीएमआर एयरोस्पेस ऐंड इंडस्ट्रियल पार्क के तौर पर जाना जाता है।

इस प्रतिष्ठान के निर्माण के लिए स्पाइसजेट ने आज जीएचएएसएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका शुरुआती आकार 33,000 वर्ग फुट होगा जिसे बढ़ाकर 1 लाख वर्ग फुट किया जा सकेगा।

स्पाइसजेट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा, 'हम अपनी कार्गो इकाई स्पाइसएक्सप्रेस का विस्तार कर रहे हैं। भारत में किसी विमानन कंपनी द्वारा अपने तरह की नई पहल के लिए जीएचएएसएल के साथ साझेदारी करते हुए स्पाइसजेट गौरवान्वित महसूस कर रही है। इससे देश में कार्गो उद्योग की क्षमता बढ़ेगी। फ्री ट्रेज जोन और स्पाइसएक्सप्रेज की शुरू से आखिर तक ही सेवाओं से हमारी साझेदार कंपनियों का कीमती समय बचेगा और उनके कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।'

हाल में स्पाइसजेट ने भारत के समुद्री कृषि उद्यान के लिए चेन्नई और विशाखापत्तनम से सूरत और कोलकाता के लिए विशेष मालवाहक उड़ान शुरू करते हुए भारत की झींगा पालन को बढ़ावा दिया है। जीएमआर एयरोस्पेस ऐंड इंडस्ट्रियल पार्क विदेशी बाजारों पर केंद्रित कारोबार के लिए तैयार औद्योगिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराती है। साथ ही यह भारतीय बाजार में आपूर्ति के लिए कारोबारियों को घरेलू शुल्क क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराती है।

विस्तार की रफ्तार धीमी रखेगी मैरियट

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 13 मार्च

दुनिया की सबसे बड़ी होटल ऑपरेटर मैरियट इंटरनैशनल भारत में अपनी विस्तार योजनाओं में कमी दर्ज करेगी, क्योंकि आर्थिक मंदी और कोविड-19 की वजह से चीन से निर्माण संबंधित आपूर्ति में समस्या की वजह से कंपनी की योजनाओं पर दबाव पड़ा है।

वैश्विक हॉस्पिटैलिटी दिग्गज ने अपने 120 होटलों के मौजूदा पोर्टफोलियो में 20 होटल जोड़ने की योजना बनाई थी। विस्तार योजना के तहत कंपनी ने कोरोनावायरस के प्रसार से पहले सात होटल खोले थे।

मैरियट इंटरनैशनल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (दक्षिण एशिया) नीरज गोविल ने कहा कि शेष होटलों का भविष्य उनके लोकेशन, निर्माण स्तरों और कुल मांग परिदृश्य पर निर्भर करेगा। गोविल ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'हब होटलों के खुलने की रफ्तार में कमी आएगी, क्योंकि इससे दो चीजें जुड़ी हुई हैं – मौजूदा मांग और आर्थिक हालात। क्या मैं ऐसे समय में होटल खोलना चाहूंगा जब मांग नहीं हो। दूसरा, चीन जैसे स्थानों से सामग्री की खरीदारी में विलंब हुआ है।'

- आर्थिक मंदी और कोविड-19 महामारी से पड़ रहा दबाव
- सभी होटलों में बुकिंग रद्द होने से बढ़ रही है चिंता

होटल और होटल डेवलपर फर्नीचर और फिक्सचर से लेकर कांच और बाथरूम फिटिंग्स तक, सभी की खरीदारी चीन से करते हैं। मैरियट वैश्विक रूप से और भारत में ऐसेट लाइट, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है।

इस बीच, यात्रा संबंधी चेतावनियों, वीजा प्रतिबंधों और भारत में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के बीच मैरियट जैसी अन्य होटल शृंखलाओं ने भी अपने सभी होटलों और ब्रांडों में ग्राहकों की संख्या में गिरावट दर्ज की है। गोविल ने कहा कि मार्च, अप्रैल और मई के लिए बुकिंग में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि होटल शृंखला ने ग्राहकों के लिए बुकिंग रद्द करने का शुल्क 31 मार्च तक माफ कर दिया है।

अपने बिजनेस होटलों की तुलना में, गोवा जैसे लीजर डेस्टिनेशंस में मैरियट के होटल अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए हैं, लेकिन इन पर प्रभाव जरूर पड़ा है। गोविल ने कहा, 'अक्सर, इस महीने में गोवा में हमारे होटल ग्राहकों के ठहरने की 90 प्रतिशत की दर हासिल करते हैं। लेकिन इस साल इसमें 40-50 प्रतिशत तक की कमी आई है।'

मैरियट ने अपने होटलों में ऐहतियाती उपायों के तौर पर अपनाए जा रहे स्वच्छता संबंधी उपायों से ग्राहकों को अवगत कराया है।

जेएलएल में होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के प्रबंध निदेशक जयदीप डांग के अनुसार, विदेशी यात्रियों पर अपनी ज्यादा निर्भरता की वजह से लक्जरी होटलों पर कोरोनावायरस का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'इस सीजन में उनका ज्यादातर व्यवसाय प्रभावित होगा।'

बिजली घरों में कोयला भंडार अब तक के उच्च स्तर पर: देश में तापीय बिजली घरों में कोयला भंडार बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 3.95 करोड़ टन तक पहुंच गया है। कोल इंडिया के अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि यह भंडार बिजलीघरों को 23 दिन तक चलाने के लिए पर्याप्त है। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के 22 दिन के ईंधन भंडार की अनिवार्यता से अधिक है। *भाषा*

बीएस बातचीत

'यह सबसे कठिन वर्ष रहा है'

लार्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी) अपनी कारोबारी योजना 'लक्ष्य 2021' से एक साल पीछे चल रहा है। इस योजना के तहत कंपनी ने 2 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा है। कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी **एसएन सुब्रमण्यन** से **अमृता पिल्लई** और **देव चटर्जी** की बातचीत के मुख्य अंश:

माइंडट्री का अधिग्रहण कैसा रहा?
वह उम्मीद के मुताबिक ही रहा है। पिछला स्वामित्व बाहर हो चुका है। अधिकतर वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। हमारे यहां कर्मचारियों की बेवजह कोई आवाजाही नहीं हुई। माइंडट्री का नेतृत्व दमदार, अच्छे ग्राहक और उनके बीच अच्छा संबंध है। कंपनी सही राह पर अग्रसर है और आगे अच्छा करेगी।

क्या आप 5 वर्षों की रणनीतिक योजना 'लक्ष्य 2021' को तैयार करने के तरीके से संतुष्ट हैं?
वह बेहतर हो सकता था। यह सबसे कठिन वर्षों में से एक है। इस दौरान हमने कुछ अजीब स्थिति देखी है जो प्रत्याशित नहीं थीं। आंध्र प्रदेश में सरकार बदलना उनमें से एक है क्योंकि उसके परिणामस्वरूप कुछ प्रमुख कार्य अटक गए। अब नई सरकार पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा करना चाहती है। यह एक झटका है क्योंकि तेजी से चल रहे कार्य इससे प्रभावित हुए हैं। हालांकि काम-काज सुचारू हो रहा है लेकिन उसकी रफ्तार कम है। दूसरा, मुंबई कोस्टल रोड और शिवाजी मूर्ति परियोजना में हमें बेवजह मुकदमेबाजी में फंसना पड़ा। इसके अलावा दिल्ली में पर्यावरण कारणों से ग्रीन ट्रिब्यूनल ने काम करना बंद कर दिया जिससे प्रगति 45 से 60 दिनों के लिए बाधित हुई। इन सब कारणों से कारोबार की रफ्तार सुस्त पड़ गई और जब आप सुस्त पड़ जाते हैं तो पुरानी रफ्तार पकड़ने में वक्त लगता है। लेकिन अब हम पटरी पर लौट चुके हैं। तीन राज्यों में चुनाव और कोरोनावायरस सहित वैश्विक आर्थिक समस्या जैसे कारकों से उद्योग प्रभावित हुआ।

कोरोनावायरस के प्रकोप से दैनिक कारोबार पर क्या प्रभाव पड़ा है?
फिलहाल उसका कोई खास प्रभाव नहीं है। चीन से सोर्सिंग के संदर्भ में थोड़ी देरी हो रही है लेकिन हमारे पास अन्य स्रोत भी मौजूद हैं। यात्रा संबंधी गतिविधियों पर रोक लग गई है और इसके कारण ग्राहक अपनी बैठक रद्द कर रहे हैं।

क्या आप वित्त वर्ष 2021 तक 2 लाख करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य को हासिल कर लेंगे?
इस लक्ष्य को लेकर हम काफी सकारात्मक हैं। हमारे ग्रुप चेयरमैन एएम नाईक ने न केवल एलऐंडटी को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई है बल्कि उसे निखारने और हमारे जैसे तमाम लोगों को लाने में भी उनका काफी योगदान रहा है। एलऐंडटी में उत्तराधिकार योजना काफी अच्छी रही है। हम योजना के तहत कार्य करते हैं, हमारे पास बजट होता है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।

पूंजी आवंटन के लिए आपकी क्या योजना है? क्या शेयर पुनर्खरीद की तैयारी की जा रही है?
फिलहाल शेयर पुनर्खरीद की कोई योजना नहीं है। यदि हमारे शेयरधारकों के हित में कोई संभावना दिखेगी तो हम उस पर सबसे पहले गौर करेंगे।

रकम जुटाने की योजना पर होगा असर

शेयरों में फिसलन के कारण प्रस्तावित सौदों को लेकर मूल्यांकन प्रतिकूल हो गया है

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 13 मार्च

भारतीय इक्विटी में हुई मौजूदा गिरावट ने रकम जुटाने की कंपनियों की योजना को प्रभावित किया है क्योंकि मूल्यांकन प्रतिकूल हो गया है और निवेशक नई कंपनी में निवेश को लेकर आशंकित हैं।

स्पेशियलिटी केमिकल कंपनी रोसारी बायोटेक और रेस्तरां शृंखला बर्गर किंग का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम इस महीने में बाजार में पेश होना था, जिसे टाल दिया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

इन कंपनियों ने क्रमश: 500 करोड़ रुपये व 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई थी। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल अपनी शेयर बिक्री के लिए जरूरी आवेदन पाने के लिए संघर्ष कर रही है जबकि कंपनी ने कीमत में कटौती की है और आवेदन की अंतिम तारीख में एक हफ्ते का इजाफा किया है।

विशेषज्ञों ने कहा कि बाजार में 20 फीसदी की गिरावट ने उन कंपनियों के सामने चुनौती पैदा की है, जो अपना आईपीओ पेश करने जा रही थी क्योंकि अब मूल्यांकन की गणना दोबारा करनी होगी। इससे ज्यादा हिस्सेदारी का विनिवेश हो सकता है या फिर इश्यू का आकार छोटा करना पड़ सकता है।

बाजार में हुए उतारचढ़ाव का साया भारतीय स्टेट बैंक की इकाई एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज की सूचीबद्धता पर भी होगा। इससे अति धनाढ्य निवेशकों के दांव पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि उन्होंने 13-15 फीसदी पर उधार लेकर इसमें आवेदन किया था। अब उन्हें मिलने वाला फायदा पहले के अनुमान के मुताबिक शायद नहीं रहेगा। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग 755 रुपये के भाव के मुकाबले 25 फीसदी छूट पर हो रहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक समय ग्रे मार्केट ऑपरेटर इश्यू प्राइस के मुकाबले 50 फीसदी प्रीमियम पर उसे खरीद रहे थे। एसबीआई कार्ड के आईपीओ को 26.54 गुना आवेदन मिला और एचएनआई श्रेणी में 45 गुना से ज्यादा बोली मिली।

विशेषज्ञों ने कहा, 24,000 करोड़ रुपये के आईपीओ पर वैध नियामकीय मंजूरी अभी भी है और अन्य आठ कंपनियां मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं। इन कंपनियों की समयसारणी में बदलाव हो सकता है क्योंकि प्राथमिक बाजार अगले कुछ महीने तक सुस्त बना रह सकता है जब तक कि द्वितीयक बाजार स्थिर न हो जाए।

प्राइम डेटाबेस के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दिया ने कहा, कोई भी कंपनी तब तक आईपीओ के बारे में विचार नहीं करेगी जब तक कि द्वितीयक बाजार में स्थिरता न आ जाए। बाजार में 10 से 15 फीसदी का बदलाव काफी अनिश्चितता और निवेशकों के बीच डर के बारे में बताता है।

मूल्यांकन पर काफी चोट पड़ी है क्योंकि बाजार में काफी गिरावट आई है और सूचीबद्ध होने पर विचार कर रही कंपनियों को संभावित मूल्यांकन में भारी कटौती झेलनी होगी। एक निवेश बैंकर ने कहा, निवेशक मोटे तौर पर वैसे आईपीओ में रकम लगाते हैं, जिसमें नई बात हो, बढ़त की संभावना हो और सूचीबद्ध कंपनियों के मुकाबले मूल्यांकन बेहतर हो। जब सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर सस्ते दाम पर उपलब्ध होंगे तो कोई भी नए शेयर में क्यों निवेश करना चाहेगा।

अहम कंपनियां मसलन रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस में 27 फरवरी से अब तक 9 से 20 फीसदी की गिरावट आई है। पीएल कैपिटल मार्केट्स के उपाध्यक्ष (निवेश बैंकिंग) दारा कल्याणीवाला ने कहा, बाजार से रकम जुटाने की इच्छा रखने वाली कंपनियां एसबीआई कार्ड्स की सूचीबद्धता से संकेत हासिल कर सकती हैं। इसकी बेहतर सूचीबद्धता न होने से अवधारणा पर और चोट पहुंच सकती है।

इसके अलावा पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) पर भी असर पड़ सकता है। हल्दिया ने कहा, आर्थिक मंदी के कारण अभी काफी ज्यादा नई पूंजी नहीं जुटाई जा रही है। अगर नई पूंजी के लिए निवेशकों के बीच स्वाभाविक इच्छा हो तब भी कोई भी कंपनी कम मूल्यांकन पर रकम नहीं जुटाना चाहेगी।

विशेषज्ञों ने कहा, अगर कीमतें दबाव में रहीं तो पुनर्खरीद और गैर-सूचीबद्धता की वापसी हो सकती है। सन फार्मा ने गुरुवार को कहा कि वह अगले हफ्ते कंपनी के शेयरों की पुनर्खरीद पर विचार करेगी। टाटा संस ने गुरुवार को समूह की चार कंपनियों के 531 करोड़ रुपये के शेयर एनएसई पर ब्लॉक डील के जरिए खरीदे।

पूंजी जुटाने की योजना

सेबी से आईपीओ की मंजूरी वाली कंपनियां	आईपीओ का अनुमानित आकार
बजाज एनर्जी	5,450
ईडियन रेलवे फाइनैंस	2,000
पन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज	1,550
होम फर्स्ट फाइनैंस	1,500
इक्विटास स्मॉल फाइनैंस बैंक	1,000
बर्गर किंग	1,000

स्रोत : प्राइमडेटाबेस, आंकड़े करोड़ रुपये में

म्युचुअल फंड निवेशकों को मिली राहत

एक महीने में लार्जकैप योजनाएं 20 फीसदी फिसल चुकी हैं

जश कृपलानी
मुंबई, 13 मार्च

म्युचुअल फंड के निवेशकों को शुक्रवार को थोड़ी राहत मिली क्योंकि बाजार में मजबूत सुधार देखने को मिला। पिछले एक महीने में इक्विटी की अहम श्रेणियों में 17 से 20 फीसदी की तेज गिरावट आई क्योंकि बाजार पर कोरोनावायरस का असर पड़ा है।

लार्जकैप योजनाओं ने एक महीने में 20 फीसदी का नकारात्मक रिटर्न दिया है। मिडकैप व स्मॉलकैप योजनाओं के एनएवी पर इस अवधि में 17 फीसदी से ज्यादा की चोट पड़ी है। उपरोक्त रिटर्न में सुधार की संभावना है क्योंकि बाजार में शुक्रवार के कारोबारी सत्र में 10.8 फीसदी की गिरावट के बाद एक दिन का सबसे बड़ा सुधार दर्ज हुआ। शुक्रवार को निफ्टी 3.8 फीसदी चढ़कर बंद हुआ।

हालांकि बाजार में हुई हालिया बिकवाली के बीच निवेशकों की अवधारणा कमजोर हुई है। म्युचुअल फंड के वितरक ने कहा, क्लाइंटों की पूछताछ बढ़ी है क्योंकि निवेशक जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें निवेश निकाल लेना चाहिए या फिर निवेशित रहना चाहिए।

उद्योग के प्रतिभागियों इससे चिंतित हैं कि बाजार में जारी उतारचढ़ाव से इक्विटी निवेश पर खासा असर पड़ सकता है। फरवरी में उद्योग ने इक्विटी योजनाओं में 10,795 करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया, जो एक महीने पहले के मुकाबले 37 फीसदी ज्यादा है।

इस बीच, एसआईपी के जरिए निवेश में फरवरी में मामूली गिरावट दर्ज हुई और कुल निवेश 8,513 करोड़ रुपये रहा। इक्विटी योजनाओं का अल्पावधि रिटर्न पिछले कुछ दिनों मे तेजी से घटा है, जब बाजार में 9 मार्च को 2,000 अंकों की गिरावट दर्ज हुई।

तब से लार्जकैप योजनाओं ने करीब 8 फीसदी का नकारात्मक रिटर्न दिया है, वहीं मिडकैप व स्मॉलकैप योजनाओं का रिटर्न 7 फीसदी घटा है।

श्रीकवि वेल्थ के मुख्य कार्याधिकारी श्रीकांत मटरूभाई ने कहा, अगर बाजार में उतारचढ़ाव जारी रहा तो कमजोर निवेशक अपने म्युचुअल फंड पोर्टफोलियो से निकलने पर विचार करेंगे। हालांकि निवेशित बने रहने वाले निवेशक अगर बाजार के उतारचढ़ाव को झेलने में सक्षम होते हैं तो लंबी अवधि में उन्हें मजबूत रिटर्न मिल सकता है।

एक फंड हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, मार्च में हुई बिकवाली वास्तव में देसी म्युचुअल फंड निवेशकों के लंबी अवधि के नजरिये की जांच करेगा। हमें यह देखना होगा कि क्या एसआईपी खाते को बंद करने के मामले में तीव्र बढ़ोतरी तो नहीं हो रही।

फरवरी में एसआईपी बंद होने का अनुपात 50 फीसदी रहा। हर दो एसआईपी खाते में से एक को बंद करने का अनुरोध मिला। फरवरी में 11.39 लाख एसआईपी खाते खुले, वहीं 5,74,000 खाते बंद हुए। कुल मिलाकर उद्योग में एसआईपी के जरिए 3.1 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्ति आती है। यह उद्योग की कुल परिसंपत्ति 27 लाख करोड़ रुपये का 11 फीसदी है।

इक्विटी योजनाओं का बिगड़ता प्रतिफल (प्रतिशत में)

प्रकार	1 महीने में	3 महीने में
लार्ज कैप	-20.4	-18.16
स्मॉल कैप	-17.8	-8.3
मिड कैप	17.3	-9.8

स्रोत : वैल्यू रिसर्च, 12 मार्च, 2020 का प्रतिफल

शेयर बाजार में तीव्र सुधार से शॉर्ट सेलर्स को लगा झटका

जश कृपलानी
मुंबई, 13 मार्च

शुक्रवार को शॉर्ट सेलर्स बुरे फंसे क्योंकि कारोबारी सत्र के शुरुआती दो घंटे के दौरान 10 फीसदी की गिरावट हुई और फिर तीन फीसदी से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ।

बाजार के प्रतिभागियों के मुताबिक, ट्रेडर उम्मीद कर रहे थे कि बढ़त पर बिकवाली की रणनीति के लिहाज से बाजार अनुकूल होगा और उन्होंने नई शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू कर दी जब बाजार ने दिन के निचले स्तर से थोड़ा सुधार दिखाना शुरू किया।

एडलवाइस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख योगेश राधके ने कहा, नए शॉर्ट कॉल वाले ट्रेडर शुक्रवार को फंस गए होंगे। बाजार में गिरावट मोटे तौर पर मार्जिन कॉल के कारण हो रही थी और ट्रेडरों ने तीव्र सुधार की उम्मीद नहीं की होगी क्योंकि उधार पर हुई खरीद की बिकवाली शुरू हो गई थी।

इसके अलावा बाजार के प्रतिभागियों ने बैंक निफ्टी की शॉर्ट कवरिंग की, जो बाजार में तेज सुधार की एक वजह रही। बैंकिंग इंडेक्स दिन के निचले स्तर से 17.9 फीसदी चढ़कर बंद हुआ।

मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख (तकनीकी व डेरिवेटिव) चंदन तापड़िया ने कहा, बाजार में शुरुआती घबराहट के बाद निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन नजर आई। इस बीच, जिन ट्रेडरों ने पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की खरीदारी के जरिए शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू की थी, वे चकित हुए। 9800 व 9900 स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी पुट ऑप्शन में शुक्रवार के कारोबार के अंत में प्रीमियम करीब 40 फीसदी घट गया।

शुक्रवार को बाजार पांच फीसदी की गिरावट के साथ खुला और पांच मिनट के भीतर निफ्टी में लोअर सर्किट लग गया। इससे 45 मिनट तक कारोबार बंद रहा। 10.15 बजे कारोबार दोबारा शुरू होने के बाद एक घंटे के कारोबार में बाजार हरे निशान में आ गया।

विशेषज्ञों ने कहा कि बाजार में नई पोजीशन बनाने में अब ट्रेडरों को सतर्कता बरतनी होगी। एक ब्रोकिंग हाउस के डीलर ने कहा, ट्रेडरों को अगले दिन के कारोबार के लिए अपनी पोजीशन को ले जाना टालना होगा। राधके ने कहा, बाजार में थोड़े समय उतारचढ़ाव रहेगा। इसके अलावा बाजार तब तक एकीकरण के चरण में बना रहेगा जब तक कि कोरोनावायरस के मामले में किसी तरह की स्पष्टता नहीं आ जाती।

तापड़िया ने कहा, ट्रेडरों को अपना पोजीशन हल्का बनाए रखने की सलाह दी गई है क्योंकि दुनिया भर में उतारचढ़ाव कई साल के उच्चस्तर पर है।

बुरे फंसे

बढ़त में बिकवाली की रणनीति वाले ट्रेडरों को पुट पर लगा झटका

निफ्टी स्ट्राइक प्राइस	ओपन इंटरेस्ट	प्रीमियम में बदलाव (%)
9800	2,37,675	-39
9900	1,22,175	-40
निफ्टी बंद	9955.2	

स्रोत : नैशनल स्टॉक एक्सचेंज

साल 2008 के स्तर से नीचे मार्जिन कॉल और उधारी

बाजार नियामक सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों की तरफ से नियामकीय ढांचे में सख्ती से परेशानी टालने में मिली मदद

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 13 मार्च

पिछले कारोबारी सत्रों में बाजार में आई तेज गिरावट से मार्जिन की मांग हुई है, लेकिन यह साल 2008 के वित्तीय संकट के दौरान हुई मांग के मुकाबले कम रही है। बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हुए नियामकीय बदलाव के कारण अत्यधिक उधारी में कमी दर्ज हुई है। पिछले कारोबारी सत्रों में मार्जिन की मांग उठी क्योंकि बड़े क्लाइंट शेयरों की बिकवाली कर रहे थे। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा कि उधारी खाते वाले पोर्टफोलियो में यह एक या दो शेयरों तक संकेंद्रित नहीं था। कुछ निवेशकों ने इस मौके का इस्तेमाल आकर्षक मूल्यांकन को देखते हुए कुछ शेयरों में किया।

कुछ ब्रोकरों ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उधार योजनाओं में कमी की और उस पर लगाम भी कसा, जो हालांकि मौजूदा नियम के तहत अनिवार्य नहीं है। नियामक ने मार्जिन की दरकार पर भी सख्ती बरती है, जिससे कारोबारी सत्र में उधारी वाली खरीदारी में अप्रत्यक्ष कमी की है।

एफवाईईआरएस के सीईओ तेजस खोड़े ने कहा, मार्जिन भुगतान, कोलेटरल और ब्रोकरों की तरफ से भुगतान पर नजर रखने की बेहर व्यवस्था इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि क्लियरिंग व निपटान की व्यवस्था बिना किसी अस्तव्यस्तता के परिचालित होगी।

1 जून 2018 से क्लियरिंग या ट्रेडिंग सदस्यों के लिए अनिवार्य बनाया गया है कि वे शुरुआती मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन या एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, मार्क टु मार्केट सेटलमेंट और कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन को शामिल करें। 1 सितंबर को अतिरिक्त निगरानी मार्जिन को लागू किया गया।

इस साल स्टॉक एक्सचेंजों ने मार्जिन ट्रेडिंग पर नई पाबंदी लगाई है और स्टॉक ब्रोकरों को अपने क्लाइंटों से अग्रिम तौर पर मार्जिन लेने को कहा गया है, चाहे नकदी का मामला हो या फिर डेरिवेटिव का। तब तक ब्रोकरों को इस बात की इजाजत थी कि वह कोलेटरल व क्लाइंटों से संबंध के आधार पर 15 से 20 गुना उधार दे सकता है। अब क्लाइंटों को एक्सचेंज के आकलन के आधार पर मार्जिन चुकाना जरूरी है। नकदी में वीएआर मार्जिन और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन अग्रिम वसूला जाना चाहिए और अन्य मार्जिन का संग्रह तब किया जाए जब स्टॉक एक्सचेंज मार्जिन के लिए कहे। वायदा व विकल्प में सदस्यों को शुरुआती मार्जिन, शुद्ध खरीद प्रीमियम, डिलिवरी मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन क्लाइंटों से अग्रिम लेना जरूरी है।

डेरिवेटिव में कारोबार करने वालों से ब्रोकर अब काफी ज्यादा मार्जिन ले रहे हैं। नई व्यवस्था इस साल 21 जनवरी से लागू हुई और यह दो दिन में होने वाले उतारचढ़ाव को कवर करने के लिए अनिवार्य है। एक्सपोजर मार्जिन की वसूली स्पैन मार्जिन के ऊपर होती है और इंडेक्स एफऐंडओ के लिए उसे बढ़ाकर 4.24 फीसदी और स्टॉक एफऐंडओ के लिए 7.07 फीसदी किया गया है।

येस बैंक की सुधार योजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी

पृष्ठ-1 का शेष

एसबीआई द्वारा येस बैंक में 26 फीसदी इक्विटी निवेश और अन्य का 75 फीसदी निवेश तीन साल तक बना रहेगा। ऐक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी अमिताभ चौधरी ने कहा, 'भारत का संपूर्ण बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र सुदृढ़ है। ऐक्सिस बैंक भारत के बैंकिंग उद्योग में दीर्घावधि की संभावनाएं देखता है और इस तंत्र में स्थायित्व प्रदान करने में योगदान का अवसर मिलने पर हम खुश हैं।'

येस बैंक पर लगी पाबंदियां अधिसूचना जारी होने के बाद तीसरे दिन शाम में हटा ली जाएगी। आरबीआई ने 5 मार्च को येस बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था और निकासी पर 50,000 रुपये की सीमा लगा दी थी। बैंक को नया कर्ज देने से भी मना कर दिया गया था। एसबीआई के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी प्रशांत कुमार को येस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। बैंक से बंदिशें हटाए जाने के सात दिन के बाद नए बोर्ड का गठन किया जाएगा। समयसीमा के हिसाब से देखें तो बैंक से पाबंदी 18 मार्च को हटाई जा सकती है और नया बोर्ड 25 मार्च को कार्यभार संभाल सकता है।

वित्त मंत्री ने अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा कि यह मामला अदालत में है। येस बैंक का शेयर 2 फीसदी बढ़कर 25.25 रुपये पर बंद हुआ।

बीएसई सेंसेक्स गिरा, फिर संभला

पृष्ठ-1 का शेष

सेंसेक्स और निफ्टी के बढ़त पर बंद होने के बावजूद यह जनवरी कके सर्वकालिक उच्च स्तर से 17 फीसदी नीचे है।अैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच में इंडिया इक्विटी स्ट्रैटजिस्ट संजय मुकीम ने कहा कि बाजार का मूल्यांकन निचले स्तर पर पहुंच गया है लेकिन इसमें अभी और गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता।भट्ट ने कहा कि दो वजहों से हम यह नहीं कह सकते हैं बाजार निचले स्तर पर पहुंच चुका है। पहला शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और दूसरा कोरोनावायरस। इसके साथ ही तेल उत्पादक देशों के बीच उत्पादन में कटौती को लेकर भी सहमति बनने के कोई संकेत नहीं हैं। कारोना की वजह कई विकसित देशों ने आवाजाही और कारोबार को सीमित कर दिया है जिससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। सुबह कारोबार के दौरान बाजार में तेज गिरावट के बीच सेबी और एक्सचेंज के अधिकारियों की बैठक हुई।

बीएस बातचीत

हालिया गिरावट के बाद आकर्षक हुआ शेयर बाजार

पिछले कारोबारी सत्रों में वैश्विक इक्विटी बाजारों के साथ भारतीय बाजारों में भी चौतरफा बिकवाली हुई है। मिरे ऐसेट मैनेजमेंट मैनेजर्स के मुख्य निवेश अधिकारी **नीलेश सुराणा** ने **पुनीत वाधवा** को दिए साक्षात्कार में कहा कि पांच साल पहले इक्विटी में ज्यादा आवंटन की शुरू हुई प्रवृत्ति आगे भी जारी रहेगी। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश...

शुक्रवार को निफ्टी के लोअर सर्किट छूने के बाद बाजार में तेज रिकवरी हुई। इसे आप कैसे देखते हैं?

कोरोनावायरस के कारण हुई हालिया गिरावट के बाद बाजार आकर्षक बन गया है। मुख्य फॉरवर्ड पीई गुणक 14.3 गुना लंबी अवधि के औसत से नीचे है। पीई गुणक पर आधारित मूल्यांकन और आकर्षक है, अगर हम इस विचार करें कि अनुमान के मुकाबले आय काफी नीचे है क्योंकि कंपनियों का लाभ पहले ही कई साल के निचले स्तर पर है और ब्याज दरें कम हैं। साथ ही बॉन्ड प्रतिफल और आय प्रतिफल के बीच अंतर साल 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के निचले स्तर पर है। आकर्षक मूल्यांकन को देखते हुए हम निवेशकों को इसे पूंजीकृत करने की सलाह देंगे। हालांकि कोरोनावायरस के पैदा हुई परिस्थिति को देखते हुए संपत्ति आवंटन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए और यह कहना भी मुश्किल है कि आय पर इसका कितना असर होगा।

क्या इस बिकवाली से एक संपत्ति वर्ग के तौर पर इक्विटी में निवेशकों का भरोसा हिल गया है?

एसआईपी के जरिए निवेश मजबूत बना हुआ है। साथ ही फरवरी में 10,700 करोड़ रुपये के निवेश के आंकड़े उत्साहजनक हैं और 11 महीने का सर्वोच्च आंकड़ा है जबकि बाजार में तेज गिरावट देखी गई है। निवेश की रफ्तार हालांकि अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इक्विटी में उच्च आवंटन की प्रवृत्ति जारी रहनी चाहिए, जिसकी शुरुआत पांच साल पहले हुई थी।

बाजार के मौजूदा परिदृश्य में पहली बार निवेश करने वालों के लिए आपकी क्या सलाह होगी?

इक्विटी में अनुशासित होकर निवेश करें और नजरिया लंबी अवधि का रखें। यह बताना महत्वपूर्ण है कि मुश्किल समय में अच्छे मूल्यांकन पर ज्यादा निवेश करने से रिटर्न में सुधार होता है। उतारचढ़ाव व गिरावट का फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका एसआईपी है।

भारत के आर्थिक संकेतकों में कब सुधार होगा?

आर्थिक गतिविधियों में सुधार धीरे-धीरे होगा, जो ब्याज दरों में कटौती का फायदा देने, सुधार और क्षेत्र विशेष की चुनौतियां दूर करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदम से आगे बढ़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को तेल की कम कीमतों का फायदा मिल सकता है और चालू खाते का घाटा कम हो सकता है, महंगाई कम हो सकती है और राजकोषीय घाटे में नरमी और जीडीपी की रफ्तार में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। ब्याज दरों में कटौती बाजार के लिए अहम है क्योंकि ब्याज दरें घटने से मांग सुधरती है, लाभ में सुधार होता है और पीई गुणक की दोबारा रेटिंग हो जाती है।

हालिया घटनाक्रम के बीच आपकी निवेश रणनीति क्या होगी?

हम पहले से जारी दो रणनीति पर अमल जारी रखेंगे। अच्छी कंपनियों के टूटे हुए शेयरों में अच्छा खासा निवेश करेंगे। चुनिंदा सार्वजनिक कंपनियों का भारांक बढ़ा है। हमारा नकदी का स्तर नीचे है। हम लार्जकैप व स्मॉलकैप के मूल्यांकन में बहुत अंतर नहीं देख रहे और करीब 70 फीसदी आवंटन लार्जकैप या मल्टीकैप फंडों में करने जबकि बाकी मिडकैप फंडों में करने की सलाह दे रहे हैं।

अभी कहां निवेश के मौके हैं?

हम बैंकों, बीमा, वाहन, स्वास्थ्य सेवा, गैस यूटिलिटीज, बिल्डिंग मैटीरियल आदि पर सकारात्मक हैं। इसके अतिरिक्त हमने कुछ अच्छे सार्वजनिक उपक्रम भी जोड़े हैं।

रुपया बचाने पर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक का जोर

अनूप रॉय
मुंबई, 13 मार्च

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को स्थानीय मुद्रा बाजार में बड़ा हस्तक्षेप किया और ऑफशोर बाजार में भी इसी तरह के प्रयास किए जाने की संभावना है। ऑफशोर बाजार में कुछ ही मिनटों में एक महीने का फॉर्वर्ड पॉइंट 50 पैसे से गिरकर 32 पैसे पर आ गया। ऑफशोर फॉर्वर्ड पॉइंट में गिरावट को ऑनशोर बाजारों में रुपये में आई तेजी से मदद मिली। रुपया प्रति डॉलर के मुकाबले 74.50 के स्तर से 73.76 पर पहुंचने में सफल रहा।

आरबीआई के एक अधिकारी ने हालांकि इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मुद्रा डीलर इसे लेकर आश्वस्त हैं कि भारतीय केंद्रीय बैंक रुपये को बचाने के लिए अपने सहज स्तर को पार कर वैश्विक परिचालन के लिए सभी सीमाओं को दूर किया है। यदि ऑफशोर के संदर्भ में हस्तक्षेप की कोशिश होती है तो यह संभवत: पहली बार होगा।

एक वरिष्ठ मुद्रा डीलर ने नाम नहीं बताने के अनुरोध के साथ कहा, 'केंद्रीय बैंक अतीत में भी छोटे छोटे उपायों के तौर पर बाजार में हस्तक्षेप करता रहा है, लेकिन शुक्रवार का कदम काफी बड़ा था।'

मुद्रा डीलर ने कहा, 'ऐसा लगता है कि वैश्विक रूप से समन्वित कदम उठाया गया है। सब कुछ पर एक साथ सकारात्मक असर दिखा। शेयर बढ़े, कच्चा तेल और धातुओं में तेजी आई, मुद्राओं में मजबूती आई, रुपये ने वास्तव में अच्छी वापसी की और ऑफशोर फॉर्वर्ड पॉइंट में कमी आई। यह संकेत दिख रहा है कि आरबीआई ऑफशोर बाजारों में हस्तक्षेप कर सकता है।' आईएफए ग्लोबल में प्रबंध निदेशक अभिषेक गोयनका ने कहा कि आरबीआई ने उस समय में भी भारी मात्रा में डॉलर बेचे जब भारी जोखिम मौजूद था। इसलिए जैसे ही धारणा पर जोखिम फिर से दिखा, रुपये को लाभ मिला।

गोयनका के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट रुपये को सुरक्षित बनाने में सफल रही है, अन्यथा यह मुद्रा कम से कम 77 पर पहुंच सकती था। आरबीआई ने अपने घरेलू हस्तक्षेप के बारे में प्रत्यक्ष रूप से कोई आंकड़ा पेश नहीं किया है, लेकिन डॉलर खरीद और बिक्री पर आंकड़ा दो महीने के अंतराल के बाद आया है। हालांकि मुद्रा डीलरों को यह संकेत मिल गया कि केंद्रीय बैंक के किसी हस्तक्षेप से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा डॉलर की लगातार खरीदारी या बिकवाली के जरिये विनिमय दर में किस तरह से बदलाव आएगा। इन बैंकों ने आरबीआई और बाजारों के बीच मध्यस्थ के तौर पर काम किया है।

हालांकि यदि आरबीआई ऑफशोर बाजारों (दुबई, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग और न्यूयार्क में स्थित) में हस्तक्षेप करता है तो उसे यह कार्य वहां स्थानीय बैंकों के जरिये करना होगा। या फिर, वह उन अन्य केंद्रीय बैंकों की मदद ले सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मलेशियाई केंद्रीय बैंक और दक्षिण कोरियाई केंद्रीय बैंक को इन बाजारों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने की क्षमताओं के लिए जाना जाता है। यह वाकई केंद्रीय बैंकों द्वारा वैश्विक तौर पर समन्वित प्रयासों का दिन था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के एक अनुसार एशियाई केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय व्यवस्था में पूंजी लगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े खतरे से मुकाबले के लिए आपात कदमों पर चर्चा की।

एयर इंडिया की बिक्री की प्रक्रिया पर पड़ी कोरोनावायरस की मार

अरिदम मजूमदार
नई दिल्ली, 13 मार्च

सरकारी विमान कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया में वायरल हमले की वजह से देरी होने जा रही है। सरकार ने एयर इंडिया खरीदने की इच्छुक कंपनियों के लिए बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख एक महीने से ज्यादा बढ़ा दी है। पहले जहां इसकी अंतिम तिथि 17 मार्च थी, अब यह बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है।

इस संबंध में शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की गई। सरकार ने अधिसूचना में कहा है, 'कोविड 19 के कारण पैदा हुई स्थिति के कारण बोली में दिलचस्पी लेने वालों की ओर से किए गए अनुरोध को देखते हुए उपरोक्त बदलाव किया गया है।'

इस मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि भारत ने 15 अप्रैल तक सभी वीजा निरस्त करके सीमा सील करने की कवायद की है, जिसके चलते यह फैसला किया गया है। प्रक्रिया में शामिल एक अधिकारी ने कहा, 'बंदी और निरस्तीकरण के बीच विदेशी बोलीकर्ताओं के लिए सामान्य कामकाज करना असंभव है। इसे देखते हुए तिथि बढ़ाई गई है।'

अधिकारी ने कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो आगे और विस्तार दिए जाने की संभावना है।

उद्योग के अधिकारियों व निवेश बैंकरों ने कहा कि मौजूदा स्थिति में बोली की प्रक्रिया सफल होने की बहुत कम संभावना है क्योंकि एयरलाइंस सहित कारोबारी घराने नगदी बचाने में लगे हुए हैं।

तीसरी बार टली बेचने की योजना

- **बोली दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 मार्च थी, अब इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया**
- **कोरोनावायरस के कारण विदेशी बोलीकर्ताओं के लिए सामान्य कामकाज असंभव**
- **स्थिति में सुधार नहीं होता है तो आगे और बढ़ेगी तारीख**

एक वैश्विक विमान कंपनी के अधिकारी ने कहा, 'वायरस के हमले का असर खत्म होने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता आने पर प्रक्रिया बहाल की जा सकती है। कोई नहीं जानता कि यह कब तक चलेगा और ऐसे में खरीदारी के बजाय हमारा जोर नकदी बचाने पर होगा।'

प्रमुख वैश्विक एयरलाइन समूह वायरस के कारण पूरी दुनिया में दबाव में हैं क्योंकि सरकारों ने यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मार्गों में बदलाव के साथ विमान उतरने पर भी रोक लगाई गई है। उदाहरण के लिए सिंगापुर एयरलाइंस के शीर्ष प्रबंधन ने फैसला किया है कि वह अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करेगा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देगा। जर्मन दिग्गज लुफ्तांसा को अपने करीब आधे विमानों की उड़ान रोकनी पड़ी है।

एयर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया में सलाह दे रही कानून फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास ने कहा कि वायरस का असर पूरी दुनिया में विलय और अधिग्रहण की प्रक्रिया पर पड़ सकता है।

बहरहाल एयरइंडिया के लेन देन की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि एयर इंडिया के बैलेंस सीट में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि भविष्य की देनदारियों व नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। एक व्यक्ति ने कहा, 'बैलेंस सीट पर मौजूदा स्थिति के असर से संभावित खरीदार बचा रहेगा, जो एयर इंडिया के कारोबार में होने वाले नुकसान से होगा।'

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति या इकाई इसका अधिग्रहण करना चाहती है उसके लिएअन्य वैश्विक एयरलाइन समूहों की तुलना में एयर इंडिया का कारोबार छोटा है।

यह तीसरा मौका है जब एयर इंडिया को बेचने को लेकर सरकार की योजना टली है।

सरकारी एयरलाइंस को बेचने के लिए सरकार ने लुभावनी पेशकश के लिए पहले कई बदलाव किए हैं।

डब्ल्यूटीओ के अनुरूप निर्यात प्रोत्साहन

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 13 मार्च

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज निर्यातकों को करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुरूप योजना को मंजूरी दे दी। यह योजना पावती पत्र आधारित मौजूदा योजना का स्थान लेगी। इस निर्णय का मकसद देश की धीमे पड़ते निर्यात में तेजी लाना है।

फिलहाल निर्यातकों के लिए निर्यात किए गए विनिर्मित उत्पादों के कच्चे मालों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और सीमा शुल्क से छूट मिलती है या उसे रिफंड किया जाता है। हालांकि कुछ कर जीएसटी के दायरे से बाहर होते हैं और निर्यातों के लिए उन्हें वापस नहीं किया जाता है। इनमें परिवहन में इस्तेमाल किए गए ईंधन पर लगने वाला मूल्य वर्धित कर, मंडी कर, विनिर्माण के दौरान उपयोग किए गए बिजली पर लगने वाला शुल्क आदि शामिल है। इन करों को निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लिए शामिल किया जाएगा।

आरओडीटीईपी योजना के तहत प्रतिपूर्ति किए जाने वाले करों में कृषि क्षेत्र में लगने वाले करों, कैप्टिव बिजली उत्पादन पर लगने वाले करों, स्टाम्प शुल्क और परिवहन में इस्तेमाल किए गए ईंधन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को भी शामिल किया जाएगा।

निर्यातकों के लिए कर प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी

मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय

- **मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4 फीसदी बढ़ाकर 21 फीसदी करने को मंजूरी दे दी जिससे खजाने पर 14,595 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा**
- **मंत्रिमंडल ने 7,660 करोड़ रुपये की लागत से 780 किलोमीटर लंबी हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी, परियोजना हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से जुड़ी है**

योजना के तहत क्षेत्रों और उत्पादों को चरणबद्ध रूप से अधिसूचित किया जाएगा और उन क्षेत्रों और मदों के लिए मौजूदा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के तहत दिए जा रहे लाभों को वापस लिया जाएगा। योजना के तहत एक अंतर-मंत्रालयी समिति प्रतिपूर्ति वाले करों और शुल्कों के लिए दरों और मदों का निर्धारण करेगी।

डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत दिया जाने वाला रिफंड स्थानांतरण योग्य शुल्क क्रेडिट या इलेक्ट्रॉनिक पावती के रूप में निर्यातकों को जारी की जाएगी जिसका लेखाजोखा इलेक्ट्रॉनिक बहीखाते में रखा जाएगा। इस योजना को एंड टू एंड डिजिटाइजेशन के साथ लागू किया जाएगा।

सरकार के इस निर्णय के बारे में मीडिया को बताते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि योजना अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादकों को एकसमान अवसर मुहैया कराएगी।

सूत्रों ने बताया कि इस योजना से सरकारी खजाने पर 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

ड्राबैक रेटों और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के साथ ही आरओडीटीईपी योजना के तहत रिफंड का निर्णय निर्यातों के लिए शून्य दर की दिशा में एक कदम है। शून्य दरों से आशय अंतिम उत्पादों के कच्च माल पर शून्य करों से है।

यह निर्णय इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है कि डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान समूह ने आदेश दिया था कि एमईआईएस वैश्विक व्यापार नियमों के मुताबिक नहीं है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों तहत बिजली, तेल, पानी पर सरकारी कर और शिक्षा उपकर जैसे कुछ निश्चित शुल्कों को रिफंड किए जाने की अनुमति है।

देश का निर्यात जनवरी में 1.66 फीसदी घटकर 25.97 अरब डॉलर का रह गया। निर्यात में लगातार छठे महीने कमी आई।

अप्रैल से जनवरी 2019-20 के दौरन निर्यात 1.93 फीसदी फिसलकर 265.26 अरब डॉलर की रह गई।

यूरिया इकाइयों को 350 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त लागत

सरकार ने आयात कम करने तथा घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 30 यूरिया विनिर्माण इकाइयों को 350 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सुनिश्चित लागत देने का शुक्रवार को निर्णय लिया। सरकार ने निर्धारित लागत बढ़ाने के लिए 2014 में ही दो अप्रैल को संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना-3 अधिसूचित की थी। हालांकि इस अधिसूचना की अस्पष्ट भाषा के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। उर्वरक उद्योग सरकार से मांग कर रहा था कि यूरिया विनिर्माण इकाइयों को अतिरिक्त निर्धारित लागत दी जानी चाहिए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने यूरिया इकाइयों के निर्धारित मूल्यों के निर्धारण हेतु संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना-3 में संशय की स्थिति दूर करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से अधिसूचना के सहज क्रियान्वयन में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप 30 यूरिया विनिर्माण इकाइयों को अतिरिक्त निश्चित लागत दी जा सकेगी।' बयान में कहा गया कि इससे यूरिया इकाइयों के एक लगातार संचालन में मदद मिलेगी और किसानों को यूरिया की निरंतर और नियमित आपूर्ति सुलभ होगी। *भाषा*

फरवरी में निर्यात ने पकड़ी मामूली रफ्तार

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 13 मार्च

निर्यात में लगातार छह महीने तक गिरावट का रुख बरकरार रहने के बाद फरवरी में 2.91 फीसदी की मामूली वृद्धि दर्ज की गई और यह 27.65 अरब डॉलर का रहा। उस महीने देश से बाहर भेजे जाने वाली खेपों पर कोरोनावायरस के प्रभाव का डर भी था इसके बावजूद निर्यात में वृद्धि हुई।

विदेशी मुद्रा की कमाई करने वाले सभी प्रमुख उत्पादों मसलन पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, रत्न एवं आभूषणों के निर्यातों में आश्चर्यजनक रूप से 20 फीसदी की कमी आई। अर्थशास्त्रियों ने चेताया है कि कोरोनावायरस के प्रभाव के कारण मार्च में दोबारा से निर्यात में संकुचन आ सकती है। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, 'आपूर्ति शृंखलाओं पर कोरोनावायरस का पड़ रहा असर आगामी महीनों में स्पष्ट तौर पर निर्यातों में कमी के तौर पर दिखाई पड़ सकता है।' फरवरी में गैर पेट्रोलियम और गैर आभूषण उत्पादों का निर्यात 6.16 फीसदी चढ़कर 21.23 अरब डॉलर का रहा।

बहरहाल, आयात में भी पिछले नौ महीने से जारी गिरावट का रुख थम गया और यह फरवरी में 2.48 फीसदी बढ़कर 37.5 अरब डॉलर का हो गया। कीमतों में कमी आने के बावजूद पेट्रोलियम के आयात में भी वृद्धि हुई। नतीजतन, व्यापार घाटा उस महीने घटकर 9.85 अरब डॉलर के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। इससे चालू खाता घाटे की अच्छे से भरपाई होगी जो पहले ही चालू वित्त वर्ष में दूसरी तिमाही में जीडीपी के 0.9 फीसदी से कम होकर तीसरी तिमाही में महज 0.2 फीसदी रह गई है। अर्थशास्त्रियों का यहां तक मानना है कि वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में चालू खाता सरप्लस की स्थिति में पहुंच सकता है। नायर ने कहा, 'समग्र तौर पर देखें तो कोरोनावायरस के असर, कच्चे तेल की कीमत में कमी और सोने की मांग में कमी से वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में चालू खाता मामूली तौर पर सरप्लस की स्थिति में पहुंच सकता है।'

गैर-तेल और गैर-स्वर्ण आयातों को देश में औद्योगिक क्षेत्र की सेहत बताने वाले संकेतक के तौर पर लिया जाता है, जिसमें 0.9 फीसदी की कमी आई। हालांकि, गिरावट की दर जनवरी के 4.7 फीसदी से नीचे आई जिससे मामूली राहत मिलती नजर आ रही है। चालू वित्त वर्ष में 11 महीनों में से सात महीने निर्यातों में कमी आई जिसके आंकड़े मौजूद हैं। वित्त वर्ष 2020 के पहले 11 महीनों में निर्यात किए जाने वाले खेपों में 1.05 फीसदी की कमी आई और यह 292.91 अरब डॉलर का रहा।

'सरकार उठाएगी सभी जरूरी कदम'

अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 13 मार्च

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक कोरोनावायरस के वैश्विक प्रसार और भारत की अर्थव्यवस्था व शेयर बाजार पर पड़ने वाले उसके असर पर नजर बनाए हुए हैं और सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

साथ ही मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा कि विभिन्न केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई कार्रवाई और महंगाई की स्थिति को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती का मामला बनता है। यह बयान रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की होने वाली बैठक के बाद आया है, जो 1 अप्रैल को होने वाली है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद हुए संवाददाता सम्मेलन के बाद सीतारमण ने कहा, 'वैश्विक बाजारों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। हम

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने उम्मीद जताई है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करेगा

स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। वैश्विक असर के कारण भारत के शेयर बाजार पर भी असर पड़ा है। वैश्विक रूप से गंभीर स्थिति देखी जा रही है। हम मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रिजर्व बैंक के साथ मिलकर हम निगरानी कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने की कवायद की जा रही है कि जरूरी कदम समय पर उठाए जाएं।'

उन्होंने कहा, 'विभिन्न क्षेत्रों के साथ संबंधित विभागों की करीब रोजाना बातचीत हो रही है। प्रभावित उद्योगों की जरूरतें पूरी करने की हम कवायद कर रहे हैं और यह कवायद की जा रही है कि सभी संबंधित विभाग अपने क्षेत्रों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करें।'

मौद्रिक नीति समिति की ओर से दरों में कटौती किए जाने के बारे में वित्त मंत्री ने कहा, 'रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि वह वैश्विक स्थिति को बहुत साफतौर पर देख रहे हैं और समय के मुताबिक फैसला किया जाएगा। मुझे भरोसा है कि वह अपनी तरफ से जरूरी कदम उठाएंगे।'

इसके पहले संवाददाताओं से बातचीत में सुब्रमण्यन ने भी कहा कि दरों में कटौती की संभावना है। उन्होंने कहा, 'इस पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। अन्य केंद्रीय बैंकों ने प्रतिक्रिया दी है और महंगाई के आंकड़े इसका समर्थन करते हैं।' उन्होंने कहा, 'हम यह भी उममीद करते हैं कि प्रमुख महंगाई दर आगे और नीचे जाएगी क्योंकि तेल की कीमतें कम हो रही हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि केंद्रीय बैंक को इन विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि पर्यटन, होटल, रेस्टोरेंट और मूवी जैसे सेवा क्षेत्र कोरोनावायरस के कारण हुई बंदी से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार इन क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रही है। सुब्रमण्यन ने कहा कि सरकार आंकड़ों पर बहुत सावधानी से लगातार देख रही है और सरकार व रिजर्व बैंक सभी जरूरी कदम उठाएंगे।

कमलनाथ ने लगाए विधायकों को कैद करने के आरोप

भाषा
नई दिल्ली/भोपाल, 13 मार्च

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए तत्पर रहने की बात करते हुए भाजपा पर कांग्रेस विधायकों को कैद में रखने का आरोप लगाया है। उधर राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की सलाह पर शुक्रवार को 6 मंत्रियों को उनके पदों से हटा दिया, जो कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। वहीं सिंधिया समर्थक बागी विधायकों का बेंगलूरु से भोपाल आने का कार्यक्रम रद्द हो गया है।

मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की सलाह पर छह मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से हटा दिया है। जिन मंत्रियों को हटाया गया है, वे इमरती देवी, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर और डॉ. प्रभुराम चौधरी हैं।'

कमलनाथ ने शुक्रवार को राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की और उन्हें एक सत्र सौंपा। पत्र में उन्होंने भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त में शामिल होने और कांग्रेस के विधायकों को कैद में रखने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा, 'कभी भी शक्ति परीक्षण किया जा सकता है। मैंने होली के मौके पर राज्यपाल को शुभकामनाएं दी हैं। हमारे 22 विधायकों को बंदी बनाकर रखा गया है। मैंने उन्हें एक पत्र सौंपकर भाजपा द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का आरोप लगाया है। मैंने मांग की है कि इन विधायकों को तुरंत रिहा किया जाए।'

शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पेशी के लिए सिंधिया समर्थक विधायक बेंगलूरु से भोपाल आने वाले थे, लेकिन सिंधिया से जुड़े सूत्रों ने कहा कि अंतिम क्षणों में सुरक्षा कारणों के चलते बागी विधायकों का बेंगलूरु से भोपाल आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है।

विचार विमर्श के बाद तय होगी विवाद से विश्वास की अंतिम तिथि

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 13 मार्च

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के संभावित विस्तार का संकेत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि करदाताओं से सुझाव लेने और योजना लागू करने के बारे में चर्चा के बाद इसकी अंतिम तिथि अधिसूचित की जाएगी।

इस योजना के तहत करदाताओं को बहुत कम वक्त दिए जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सीतारमण ने यह कहा। इस योजना के लिए 31 मार्च को अंतिम तिथि तय की गई है, जबकि उसके बाद कर भुगतान करने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। राज्यसभा ने आज विधेयक पारित कर दिया और अधिसूचना से पहले इस पर राष्ट्रपति के अनुमोदन की जरूरत होगी। इसकी वजह से प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए करदाताओं को बमुश्किल एक पखवाड़े का वक्त मिलेगा।

यह योजना 30 जून तक खुली रहेगी, लेकिन 31 मार्च के बाद योजना में हिस्सा लेने वालों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर भुगतान की जरूरत होगी।

सीतारमण ने कहा, 'बहरहाल विधेयक में सरकार को अंतिम तिथि अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। करदाताओं के सुझाव और पूरी प्रक्रिया पर विचार के बाद इसके बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी।'

इस योजना के तहत कर अधिकारियों को 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने को लेकर हो रही आलोचना पर सीतारमण ने कहा कि यह लक्ष्य गतिविधियां बढ़ाने के मकसद से दिया गया है, न कि हर करदाता को इसमें शामिल करने के लिए ऐसा किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, 'निश्चित रूप से हम यह चाहते हैं कि सरकार की हर योजना को अधिकारी गंभीरता से लें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर करदाता को इस योजना में शामिल किया जाना है।' उन्होंने कहा कि इसके लिए अभियान चलाया जाएगा कि करदाताओं को इसमें क्यों शामिल होना चाहिए।

> योजना की समाप्ति की तिथि सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी और इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। यह योजना विवादों के निपटारे के लिए करदाताओं को एक विकल्प मुहैया कराने के लिए है। सरकार विधेयक के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए सभी भाषाओं में राज्यों को एक परिपत्र भेजेगी

उन्होंने यह भी साफ किया कि छापा अभियानों में अगर जब्त रकम 5 करोड़ रुपये तक है तो वैसी स्थिति में संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इससे ऊपर राशि की धोखाधड़ी और कर चोरी को योजना से बाहर रखा गया है।

इस योजना में 4,00,000 से ज्यादा कर मामले शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें कम से कम 9.3 लाख करोड़ रुपये फंसे हैं।

शार्दूल अमरचंद मंगलदास ऐंड कंपनी के पार्टनर गौरी पुरी ने कहा कि इससे लगता है कि सरकार जमीनी स्थिति पर नजर रखे हुए है और वह योजना को लेकर चिंताओं को दूर करने की कवायद कर रही है।

सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार कर अधिकारियों के विवेकाधिकार और भौतिक हस्तक्षेप कम करके कर विवाद के मूल कारणों का समाधान करने की कवायद कर रही है।

डेलॉयट इंडिया के पार्टनर रोहिंटन सिधवा ने कहा कि पहले तय की गई 31 मार्च तिथि करदाताओं को योजना का लाभ उठाने के लिए बेहद कम है। योजना के लिए आए फॉर्म को भरना होगा और इसके लिए तय अधिकारी 15 दिन में राशि के बारे में फैसला करेंगे। उसके बाद करदाता को कर भुगतान और अपील वापस लेने के लिए 15 दिन और मिलेंगे। बहरहाल संसद की मंजूरी में देरी की वजह से करदाताओं को त्वरित कदम उठाने की जरूरत होगी।

इस स्पष्टीक्रण के बाद करदाताओं को थोड़ा वक्त मिलने की उम्मीद है, इस विधेयक को लागू किया जाना अभी बाकी है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 23

वित्तीय जगत और घोटाले

रजत गुप्ता ने अपनी किताब 'माइंड विदाउट फियर' में यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि वह दोषी नहीं बल्कि पीड़ित हैं। मैकिंजी के भूतपूर्व बॉस का कहना है कि न्यूयॉर्क के अभियोजक उनके पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि वे वर्ष 2008 के वित्तीय घोटालों के बड़े जिम्मेदारों को नहीं पकड़ सके। उनका कहना है कि वे उन जैसे छोटे मोटे लोगों को पकड़कर सफलता दर्शाना चाहते थे। यह सच है कि बड़े निवेश बैंक चलाने वाले लोग धोखाधड़ी और छल-कपट में शामिल थे और बच निकले। परंतु इसमें कुछ भी नया नहीं था। अक्सर वित्तीय क्षेत्र के बड़े धोखेबाज यूं ही बच निकलते हैं। ब्याज दरों के निर्धारण की दृष्टि से अहम लाइबोर (लंदन इंटर-बैंक ऑफर्ड रेट) बाजार में छेड़छाड़ का सिलसिला दो दशक से अधिक समय तक चलता रहा। लेकिन एक ही यूबीएस कारोबारी को दंडित किया गया। इसी प्रकार 2008 के वित्तीय पतन के बाद मात्र एक छोटे कारोबारी को अवैध गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया।

यदि येस बैंक और राणा कपूर को ध्यान में रखते हुए देश के वित्तीय घोटालों की बात की जाए तो बैंक के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। यह मामला वर्ष 2018 में आईएलऐंडएफएस के पतन के मामले से कतई अलग नहीं है। इससे जुड़े बड़े खिलाड़ियों से अब तक कोई सवाल तक नहीं किया गया है, अभियोजन की बात तो दूर है। यदि देश में सभी धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ मामला चले तो अत्यधिक दबाव के चलते देश में अभियोजन की व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। जैसा कि वित्तीय जगत में हो रहा है, यदि एक व्यक्ति अकेले ही एक बड़ी फर्म को ध्वस्त कर सकता है तो ऐसे में अपने पैसे के लिए किस पर यकीन किया जाए? वैश्विक निवेश फर्म बैरिंग सिंगापुर में एक धोखेबाज कारोबारी के कारण ढह गई थी। प्रश्न यह है कि जब एक पूरा संस्थान भ्रष्ट हो जाता है तो उस दौरान नियामक क्या कर रहा होता है? डॉयचे बैंक एक समय जर्मन प्रतिष्ठान का स्तंभ हुआ करता था। डेविड एनरिच ने अपनी हाल में जारी पुस्तक 'डार्क टावर्स' में विस्तार से बताया है कि डॉयचे बैंक धनशोधन से लेकर बाजार में छेड़छाड़ करके अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने, रूसी कुलीनों से समझौते करने तथा अधिकारियों और नियामकों को रिश्वत देकर सरकार को धोखा देने जैसे कामों में लिप्त था।

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

देश के जमाकर्ताओं और निवेशकों को अब पता चल रहा है, वित्तीय जगत बहुत खतरनाक स्थान है। बैंकों का पतन हो सकता है, बाजार से छेड़छाड़ की जा सकती है, निवेश संबंधी उपाय रातोरात महत्त्वहीन हो सकते हैं, अंकेक्षक चेतावनी देने से चूक सकते हैं, बोर्ड निदेशक असावधान हो सकते हैं और नियामक अक्षम साबित हो सकते हैं। परंतु चिंता करने की क्या बात है, क्योंकि भारतीयों के पास सरकारी बैंकों के रूप में सुरक्षित ठिकाने तो हैं ही? दिक्कत की बात केवल यह है कि इन सुरक्षित ठिकानों की अपनी लागत है और इसमें ढेर सारा पैसा लगता है। पांच वर्ष पहले जब सरकारी बैंकों में समस्या शुरू हुई तब सरकार ने घोषणा की कि वह सन 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद का सबसे व्यापक सुधार पैकेज पेश कर रही है। सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया। पांच वर्ष बाद सरकार उस राशि का पांच गुना बैंकों को दे चुकी है और अभी और राशि दी जा सकती है। बचतकर्ताओं का पैसा तब तक सुरक्षित है जब तक करदाता बोझ उठा रहे हैं। निजी बैंक भी सुरक्षित हैं क्योंकि भारत में बैंक नाकामी मुश्किल है। कई निजी बैंक अन्य बैंकों में समाविष्ट हो गए। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, सेंचुरियन बैंक, टाइम्स बैंक आदि इसका उदाहरण हैं। खुशकिस्मती से ये सभी छोटे बैंक थे। यदि बड़े बैंक नाकाम हों तो? यह कहा जा चुका है कि बेहतर प्रबंधकों की जरूरत है ताकि सरकारी बैंक निजी क्षेत्र से लोगों को काम पर रख सकें। परंतु राणा कपूर तो बैंक ऑफ अमेरिका में कई वर्ष रहे थे। येस बैंक में उनका स्थान डॉयचे बैंक के एक बदकिस्मत अधिकारी ने लिया और आईएलऐंडएफएस का संचालन सिटी बैंक के एक पूर्व बैंकर के हाथ में था।

ऐसी स्थिति में कोई राहत नजर नहीं आती। बाजार की समझ बढ़ाने और शुरुआती चेतावनियों पर ध्यान देने के साथ-साथ जवाबदेही बढ़ाने और अभियोजन में सुधार लाने, ढांचागत व्यवस्था और आंतरिक निर्भरता को लेकर समझ बढ़ाने की जरूरत है। केवल ऐसा करके ही भरोसा बहाल किया जा सकता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको वह करने पर मजबूर करता है जो आप नहीं करना चाहते। वित्तीय जगत में अगला घोटाला हमेशा तैयार रहता है।

बिनय सिन्हा

पेशेवर क्षेत्र को बदल रही है नई तकनीक

विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे पेशेवरों के प्रति समाज में बढ़ते गुस्से के बीच काफी संभव है कि नई तकनीक और कृत्रिम मेधा इन्हें काफी हद तक बदल दे। जानकारी प्रदान कर रहे हैं अजित बालकृष्णन

मैं ऐसी सुर्खियों को स्तब्ध होकर देखता रह जाता हूं: गत जून की एक सुर्खी कहती है कि भारत में 8 लाख चिकित्सक बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इस नवंबर की एक सुर्खी के अनुसार पुलिस के दमन के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली की तमाम अदालतों के अधिवक्ताओं से हड़ताल पर जाने को कहा। वहीं गत दिसंबर की एक खबर की सुर्खी है: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने अस्थायी शिक्षकों के समायोजन की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया।

मैं भारत के एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मेरे पिता और दादा चिकित्सक थे, मेरे चाचा-चाची और चचेरे भाई-बहिन या तो चिकित्सक थे या कॉलेज में प्रोफेसर अथवा इंजीनियर। हम अन्य परिवारों की ईर्ष्या का केंद्र थे। लोगों के भीतर इन्हें लेकर सराहना का भाव रहता और पारंपरिक विवाह बाजार में उनकी अच्छीखासी कदर होती। आखिर ऐसे विवाह ही तो किसी व्यक्ति का सही आकलन पेश करते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया लेकिन मैं इस बात की कल्पना तक नहीं कर पाया कि उनमें से कोई जीवन में कुछ हासिल करने के लिए हड़ताल पर जाएगा। हड़ताल पर जाने का काम मिल मजदूर और बोझ उठाने वाले करते थे। देश में चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, प्रोफेसरों और इंजीनियरों का वेतन बाकी कर्मियों से काफी बेहतर रहता था। यदि उन्हें आवश्यकता महसूस होती तो उनके वेतन में कुछ सुधार कर दिया जाता। उन्हें इसके लिए बस मुख्यमंत्री या सचिवों के कान में फुसफुसाकर अपनी बात कहनी होती थी और काम बन जाता था।

ये ऐसे पेशे थे जिनकी देश का मध्यवर्गीय युवा आकांक्षा करता था। ये युवा कड़ी मेहनत करते थे ताकि वे प्रतिस्पर्धी परीक्षा पास कर सकें और उनके सामने करियर के दरवाजे खुल सकें। ये पेशे प्रतिष्ठित माने जाते थे और देश के तमाम आर्थिक प्रयोगों से गुजरने के दौरान भी ये प्रतिष्ठित बने रहे। इस बीच देश की अर्थव्यवस्था सरकारी से बाजार आधारित हो गई। इस बीच तमाम राजनीतिक प्रयोग भी हुए (कांग्रेस से वाम और सामाजिक समूह आधारित दलों तक)। इसके अलावा सामाजिक प्रयोग भी हुए और महिलाएं मुख्यमंत्री और बड़े वित्तीय संस्थानों की प्रमुख बनीं।

ये तमाम पेशे बीते 50 वर्ष में कई चरणों से गुजरे हैं। आजादी के वक्त कोई भी अच्छा चिकित्सक या इंजीनियर आगे की पढ़ाई के लिए इंगलैंड जाता, उसकी पढ़ाई का खर्चा परिवार उठाता और वापस लौटकर वह एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीता। सन 1960 के दशक में देश में विश्वविद्यालय व्यवस्था का विस्तार हुआ, इन पेशों के स्नातक अमेरिका, इंगलैंड या ऑस्ट्रेलिया का रुख करने लगे जहां ऐसे पेशेवरों की कमी के चलते इनकी भारी मांग थी। अभी हाल तक इन पेशेवरों का जीवन काफी सुरक्षित नजर आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ?

भारत में चिकित्सकों पर हमले नए नहीं हैं। इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री के एक विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका में चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा के मामलों में 57 फीसदी आपातकालीन कर्मियों को हथियार से डराया गया। यूनाइटेड किंगडम में 52 फीसदी चिकित्सकों ने कहा कि उनके साथ किसी न किसी तरह की हिंसा हुई। चीन, इजरायल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ऐसे ही आंकड़े सामने आए।

अमेरिका के नॉर्थईस्टर्न विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर एलियट क्रॉज ने उन चुनौतियों का विश्लेषण किया जो आधुनिक पेशों के समक्ष आती हैं। गौरतलब है कि चिकित्सा, कानून, शिक्षण और इंजीनियरिंग आदि पेश कुल पेशों का 60 फीसदी हैं। उनका कहना है कि ये व्यापारिक गिल्ड हैं। वह कहते हैं कि मध्ययुगीन बुनकरों और सूत कातने वालों की गिल्ड की तरह ये पेशे और उनके एसोसिएशन अपने हुनर को एक रहस्यात्मकता प्रदान करते हैं जहां कॉर्पोरेट एकाधिकार कायम करने का आर्थिक लक्ष्य होता है वहां दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। डेथ ऑफ द गिल्ड्स नामक अपनी पुस्तक में वह लिखते हैं कि हालांकि अतीत में ये पेशे ताकतवर रहे हैं लेकिन बीते दशक में उपभोक्ताओं की सक्रियता की बदौलत नीति निर्माताओं में इन पेशों के प्रति समानुभूति कम हुई है और किफायत और सेवाओं की गुणवत्ता पर जोर बढ़ा है।

चिकित्सकों की हड़ताल को मीडिया में मिलने वाली कवरेज भी मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा उन पर होने वाले हमलों तक सीमित रहती है। अधिवक्ताओं की हड़ताल में ध्यान पुलिस की कड़ी कार्रवाई पर तो शिक्षकों की हड़ताल में मीडिया का ध्यान उनकी स्थायी कर्मचारी बनने की चाह पर केंद्रित रहता है।

मैं इसकी तुलना सन 1980 के दशक के बंबई से करना चाहता हूं जब अचानक कई दर्जन टेक्सटाइल मिलों में हड़ताल की खबरें सुर्खियों में आ गई थीं। उस वक्त ऐसा दर्शाया गया मानो ये हड़ताल कामगारों की उच्च वेतन की 'अतार्किक' मांग और 'आक्रामक' मजदूर नेता दत्ता सामंत जिम्मेदार थे। एक वर्ष के भीतर इनमें से 80 मिलें बंद हो गईं और 2.50 लाख कर्मचारी बेरोजगार हो गए। समय बीतने के साथ हम ज्यादा साफ देख पाए कि हुआ क्या है। नायलॉन और पॉलिएस्टर के आगमन ने बंबई की कॉटन का कपड़ा बनाने वाली मिलों को नुकसान में धकेल दिया। मिल मालिकों को अपने मजदूरों को वेतन देने तक के पैसे नहीं थे, बोनस और वेतन वृद्धि तो दूर की कौड़ी है। असली खलनायक दत्ता सामंत नहीं बल्कि कृत्रिम धागों की नई तकनीक थी।

जिस प्रकार कृत्रिम धागों ने कपड़ों को सबकी पहुंच तक पहुंचाया, वहीं अब कृत्रिम मेधा में भारी भरकम निवेश हो रहा है। इससे ऐसे कई काम स्वचालित हो जाएंगे जिन्हें अभी पेशेवरों द्वारा अंजाम दिया जाता है।

चिकित्सा क्षेत्र में कृत्रिम मेधा की तकनीक बीमारियों का पता लगाने में काफी सहायक सिद्ध हो रही है। उदाहरण के लिए लिम्फ नोड टिश्यू में स्तन कैंसर का पता लगाना। विधिक क्षेत्र में अनुबंध समीक्षा और वाद के नतीजे के अनुमान लगाने में यह काम आ रहा है। हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय ने पहले ही डिजिटल मानविकी में पाठ्यक्रम शुरू किया है। ऐसे में काफी संभव है कि चिकित्सा सुविधा, विधिक और शैक्षणिक सेवाएं जल्दी ही और अधिक सस्ती होंगी लेकिन यह इस पेशे के कई लोगों की आय को प्रभावित भी कर सकता है।

शायद अब आवश्यकता आ गई है कि मशीन लर्निंग अलगोरिद्म को चिकित्सा महाविद्यालयों, विधिक और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और यहां तक कि वाणिज्य और मानविकी क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाया जाए। इससे युवा भारतीय उभरते विश्व में अधिक विश्वास के साथ कदम रख सकेंगे।

ठोस उपाय करने से ही थमेगा समाचार चैनलों पर वैमनस्य

मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

कुछ दिन पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दो समाचार चैनलों- एशियानेट न्यूज और मीडियावन- पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया था। मंत्रालय का तर्क था कि इन दोनों चैनलों ने दिल्ली में हुए दंगे से जुड़ी सामग्री का प्रसारण अनुचित तरीके से किया, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेग्युलेशन) अधिनियम, 1995 के तहत वर्णित नियमों के अनुरूप नहीं था। मंत्रालय का कहना था कि इन चैनलों ने जिस तरह दंगे से जुड़े समाचारों का प्रसारण किया था, उससे समाज में कटुता पैदा हुई। दंगे में 50 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों बेघर हो गए। दोनों चैनलों ने मंत्रालय के निर्णय पर सवाल खड़े किए। मंत्रालय ने एक दिन बाद ही प्रतिबंध हटा दिया।

मंत्रालय की यह कार्रवाई महज दिखावा ही कही जा सकती है। दिल्ली में मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं ही बोली जाती हैं। मलयालम भाषा के इन दोनों चैनलों के दर्शकों की संख्या दिल्ली में नाम मात्र है। दूसरी तरफ हिंदी और अंग्रेजी समाचार चैनल अक्सर समाज को बांटने वाली खबरें प्रसारित करते रहते हैं और हरेक घटना को अनावश्यक रंग चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में घृणा भाषण को ऐसे भाषण या लेखन के तौर पर परिभाषित किया गया है, जो किसी खास समूह के लोगों पर प्रजाति, धर्म या यौन आचरण के आधार पर हमला करता है या धमकी देता है। राजनीतिज्ञ जब समाज को बांटने वाले भाषण देते हैं तो उन पर शायद ही कड़ी कार्रवाई होती है। समाचार चैनलों पर समाचार प्रस्तोता (न्यूज एंकर) लगभग हर रोज वैमनस्य एवं समाज को बांटने वाले समाचार बिना किसी संकोच के प्रसारित करते रहते हैं। इस तरह की गतिविधियां केबल अधिनियम का उल्लंघन करती हैं, लेकिन इसे लेकर सरकार ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई है।

कुछ अपवाद जरूर हैं, लेकिन मोटे तौर पर भारतीय न्यूज टेलीविजन और इसके न्यूज एंकरों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम धूमिल किया है। भारतीय न्यूज चैनल और उनके न्यूज एंकर न केवल भारत में हास्य व्यंग्य के पात्र बन गए हैं, बल्कि विदेश में भी दूसरे देशों के पत्रकार इनकी खिल्ली उड़ाते हैं। आखिर नौबत यहां तक कैसे आ पहुंची है? टेलीविजन की पहुंच 83.6 करोड़ भारतीयों तक है। इसकी तुलना में इंटरनेट की 66 करोड़ और अखबारों की 40 करोड़ लोगों तक ही पहुंच है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस काउंसिल रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार इनमें समाचार चैनलों की पहुंच 26 करोड़ लोगों तक है। करीब 5 से 10 करोड़ लोग इंटरनेट के माध्यम से भी समाचार देखते हैं। वर्ष 2000 में समाचार चैनलों की तादाद करीब 10 थी और यह संख्या बढ़कर 400 से अधिक हो गई है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। ऐसे चैनलों की आई बाढ़ के बीच 24 घंटे समाचार दिखाने वाले चैनलों की मांग, प्रशिक्षण का अभाव, राजस्व पर निर्भरता और उलझे मालिकाना हक हालात और पेचीदा बना देते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि एक भारतीय समाचार प्रसारण बाजार का जन्म हुआ है।

हालत यह है कि फर्जी समाचार वेबसाइटों और भारतीय समाचार चैनलों के बीच अंतर ना के बराबर रह गया है। फर्जी समाचार वेबसाइट चौकाने वाली सुर्खियां लगाते हैं और भारतीय समाचार चैनल और इनके न्यूज एंकर दर्शकों को बांधे रखने के लिए नाटकीय तरीके से खबरें परोसते हैं। समाचार चैनल किसी घटना को कितना भी बढ़ा चढ़ाकर या नाटकीय तरीके से पेश क्यों न करें, उन्हें वित्तीय तौर कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। टेलीविजन उद्योग 74,000 करोड़ रुपये का है, जिनमें समाचार टेलीविजन की हिस्सेदारी मात्र 3,000-4,000 करोड़ रुपये है। इनमें भी कुछ ही समाचार चैनल मुनाफा कमा पा रहे हैं। हालांकि ये जो दिखाते हैं, उनका समाज पर व्यापक असर जरूर पड़ता है। अन्य नुकसान के साथ ही ये भारत की विविधता की छवि को भी तार-तार कर रहे हैं। भारत ऐसा देश रहा है, जिसके बुद्धिजीवियों और मुख्य कार्याधिकारियों का विदेश में स्वागत किया जाता है।

विडंबना यह है कि ये हालात उन चैनल मालिकों के तहत ही हुए हैं, जिन्होंने पिछले 50 वर्षों में देश को बेहतरीन मीडिया ब्रांड दिए हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए निश्चित तौर पर प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है। सबसे पहले मालिकाना हक में बदलाव की जरूरत है। गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता और अन्य दबावों के बीच किसी एक को चुनने की बात आती है तो मालिकाना हक संबंधी शर्तें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दुनिया के कुछ श्रेष्ठ न्यूज ब्रांड- द इकॉनमिस्ट, द न्यू यॉर्क टाइम्स, फाइनैंशियल टाइम्स- पर ट्रस्ट का नियंत्रण है।

दूसरा उपाय यह है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए। एक स्वतंत्र सार्वजनिक प्रसारक समाचार बाजार में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। बीबीसी का नाम इस लिहाज से अहम है। इसने न केवल ब्रिटेन के लोगों तक निष्पक्ष भाव से खबरें पहुंचाई हैं, बल्कि वहां निजी समाचार प्रसारकों पर भी नियंत्रण रखा है। तीसरे उपाय के तहत एफएम रेडियो चैनलों को समाचार प्रसारित करने की अनुमति दी जा सकती है। इससे एक और समाचार माध्यम सामने आएगा, जिसकी पहुंच बड़ी संख्या में लोगों तक होगी।

अंत में कुछ जिम्मेदारी दर्शकों और विज्ञापनदाताओं की भी बनती है। क्या दर्शक एवं विज्ञापनदाता उन चैनलों से दूरी बना सकते हैं, जो समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं? यहां पर यह तर्क दिया जा सकता है कि समाचार चैनल इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इससे उन्हें अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलती है। पिछले तीन वर्षों में कुछ खास हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार चैनलों के दर्शकों की संख्या एवं विज्ञापन राजस्व में इजाफा हुआ है। कुछ भी हो, लेकिन घृणा फैलाने वाले समाचारों से शायद ही देश का भला हो। अगर करोड़ों दर्शक ऑनलाइन या प्रिंट माध्यम में से बेहतर विकल्पों का चयन कर सकते हैं और विज्ञापनदाता दूरी बनाए रखना शुरू करें तो क्या यह घृणा, दर्शक, राजस्व, धुव्रीकरण का सिलसिला तोड़ सकते हैं?

कानाफूसी

कांग्रेस को फिर झटका

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने गुरुवार को बिहार की दो राज्य सभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि उसके और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस उसकी साझेदार है और एक सीट की मांग कर रही थी। राज्य सभा में खाली हो रही पांच सीटों में से दो के लिए राजद ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। वे हैं प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह। गुप्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी हैं और फिलहाल झारखंड से राज्य सभा सदस्य हैं। उनका कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। सिंह पटना के एक बड़े उद्योगपति हैं और माना जा रहा है कि राजद उन्हें प्रत्याशी बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उच्च जाति के लोगों को लुभाना चाहती है।

आजाद बनाएंगे नई पार्टी

भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रविवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अपने राजनीतिक दल की शुरुआत की घोषणा कर सकते हैं। उस दिन बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक कांशी राम की जन्मतिथि भी है। नए राजनीतिक दल के लिए जो संभावित नाम तय किए गए हैं वे हैं- आजाद समाज पार्टी, आजाद बहुजन पार्टी और बहुजन अवाम पार्टी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नाम पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद लिया जाएगा। माना जा रहा है कि पार्टी रविवार को ही अपना घोषणापत्र और सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेगी। भीम आर्मी अपनी छात्र शाखा भीम आर्मी स्टूडेंट्स फेडरेशन की भी शुरुआत कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक नए राजनीतिक दल की शुरुआत के बाद भीम आर्मी एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करेगी। जाहिर है बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती इन घटनाओं पर करीबी नजर रखेंगी।

आपका पक्ष

ई-कॉमर्स में फर्जी विक्रेताओं से सावधान

देश और दुनिया में कई तरह के ऑनलाइन व्यावसायिक मंच उपलब्ध हैं। ऐसे ई-कॉमर्स मंचों से क्रेता किसी विक्रेता के उत्पादों को आसानी से खरीद सकता है। ऐसी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा किसी उत्पाद को खरीदने-बेचने के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन बताया जाता है कि कुछ मामलों में विक्रेताओं का सही ढंग से सत्यापन नहीं होता है। इससे फर्जी विक्रेता काफी संख्या में ऐसी ऑनलाइन कंपनियों से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन मंचों पर फर्जी विक्रेताओं की संख्या काफी है जो लगातार ग्राहकों को ठग रहे हैं। ऐसी खबरें आती हैं कि ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से फर्जी विक्रेताओं ने ग्राहकों को ठग लिया। इससे ग्राहकों को तो नुकसान होता ही है, साथ ही ऑनलाइन कंपनियों की साख भी कम होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो दुनिया की बड़ी ऑनलाइन कंपनियों में शामिल एक विदेशी ऑनलाइन कंपनी में फर्जी विक्रेताओं की काफी संख्या में होने का पता चला है। उक्त कंपनी अपने विक्रेताओं का सही ढंग से सत्यापन करने में असफल रही है। इसका फायदा उठाकर फर्जी विक्रेता ग्राहकों को ठग रहे हैं जिससे दिन प्रतिदिन उस कंपनी की साख गिर रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऑनलाइन कंपनियों पर यह दायित्व नहीं बनता है कि वे अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करें तथा कंपनी के प्रति उनका विश्वास बनाए रखें। इसके लिए ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों को अपने सभी विक्रेताओं का सत्यापन कराना जरूरी है। इसके अलावा विक्रेता कितने वर्षों से कारोबार कर रहा है यह पता लगाना जरूरी है।

ई-कॉमर्स कंपनियों से उत्पाद खरीदते समय ग्राहकों को सावधानी बरतनी चाहिए

विमलेंद्र मणि त्रिपाठी, गोरखपुर

कोरोनावायरस से आजीविका पर संकट

कोरोनावायरस चीन की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। इस वायरस के परोक्ष प्रभाव के कारण वाराणसी में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों की आजीविका पर संकट के बादल दिख रहे हैं। कच्चे माल के लिए चीन पर बढ़ती निर्भरता का खमियाजा देसी उद्योग भुगत रहे हैं। भारत में करीब-करीब सारे उद्योग इस वायरस के शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं इसका भारतीय शेयर बाजार पर भी गंभीर प्रभाव दिखाई दे रहा है। केंद्रीय बैंक के आश्वासन के बाद भी शेयर बाजार में सुधार नहीं आया तथा यह लगातार गिर रहा है। भारत में भी कई जगहों पर कोरोनावायरस से संक्रमित मरीज की पहचान होने लगी है। ऐसे में सरकार को अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए कोरोनावायरस से निपटने के लिए सभी तरह के उपाय करने चाहिए।

संध्या कुमारी, गोरखपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

कच्चे तेल में सुधार लेकिन गिरावट का दौर जारी

भाषा
सिंगापुर, 13 मार्च

कीमतों को लेकर मचे घमासान तथा कोरोनावायरस संक्रमण से जुड़ी चिंताओं के बीच आज कच्चे तेल में चार प्रतिशत तक की तेजी रही। हालांकि, यह अभी भी एक दशक से अधिक की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट की राह पर बढ़ रहा है। कच्चे तेल के कारोबार में शुक्रवार को भी उथल-पुथल जारी रही। शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टैक्सस इंटरमीडिएट दोनों के वायदा भाव में दो प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि, एशियाई बाजारों में मध्याह्न कारोबार में दोनों की चाल में सुधार हुआ। वेस्ट टैक्सस इंटरमीडिएट चार प्रतिशत चढ़कर 33 डॉलर प्रति बैरल पर और ब्रेंट क्रूड 3.9 प्रतिशत उछलकर 34.50 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

शेयर बाजारों में तेजी तब आई जब अमेरिका की सेना ने इराक में हवाई हमले करने शुरू किए। इससे कच्चे तेल को मजबूती मिली। एशियाई शेयर बाजारों के गिरावट से उबरने तथा यूरोपीय शेयर बाजारों की ठोस शुरुआत से भी कच्चे तेल को समर्थन मिला। हालांकि, साप्ताहिक आधार पर वेस्ट टैक्सस इंटरमीडिएट में अभी भी 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट बनी हुई है। यह 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है।

ब्लूमबर्ग की खबर के अनुसार, ब्रेंट क्रूड में सप्ताह के दौरान करीब 25 प्रतिशत की गिरावट हुई है। कच्चा तेल के शीर्ष उत्पादक सऊदी अरब और रूस के बीच आपूर्ति सीमित करने को लेकर सहमति नहीं बनने के बाद दोनों देशों में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद सऊदी अरब ने जानबूझकर कच्चे तेल की कीमतें गिराने के लिए उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने की घोषणा कर दी।

संयुक्त अरब अमीरात ने भी सऊदी अरब का साथ देते हुए उत्पादन व आपूर्ति बढ़ाने की बात की। इससे कच्चे तेल की कीमतें भरभरा गईं और इनमें 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई।

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट

दामों में गिरावट के बावजूद खरीदारों ने अब भी बना रखी है बाजार से दूरी

राजेश भयानी
मुंबई, 13 मार्च

पिछले कुछेक महीने के दौरान सुरक्षित निवेश के रूप में उभरे सोने में आज काफी गिरावट नजर आई, जबकि शेयर बाजार में तीव्र गिरावट के बाद तेजी से सुधार हुआ है। इस सप्ताह सोने के दामों में प्रति 10 ग्राम 3,000 रुपये से ज्यादा और चांदी के दामों में प्रति किलोग्राम 4,000 रुपये से ज्यादा गिरावट आ चुकी है। निवेशकों ने मार्जिन की कमी या अन्य परिसंपत्ति वर्ग में नुकसान की भरपाई के लिए सोने की बिक्री की है।

अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों समेत जिन कारोबारियों ने इस साल सोने के दामों में तेजी आने से लाभ कमाया है, उन्होंने पैसे के लिए या तो मुनाफा वसूली की है या फिर उन्हें अन्य परिसंपत्तियों में हुए नुकसान अथवा मार्जिन में आई कमी को पूरा करने के लिए सोना बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

मुंबई के हाजिर बाजार में सोना 3.1 प्रतिशत या 1,351 रुपये तक गिरकर प्रति 10 ग्राम 41,849 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। प्रतिशत के हिसाब से सोने में आज आई यह गिरावट नवंबर 2015 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट और स्थिर मूल्य के लिहाज से अगस्त 2013 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। चांदी करीब पांच प्रतिशत की दर से 2,225 रुपये गिरकर 43,085 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई।

सोने चांदी के दाम

दिन	स्टैंडर्ड सोना रुपये/10 ग्राम	चांदी रुपये/किलो
6 मार्च 2020	44,237	47,125
9 मार्च 2020	43,838	46,005
11 मार्च 2020	43,473	46,005
12 मार्च 2020	43,200	45,340
13 मार्च 2020	41,849	43,085
अंतर प्रतिशत*	-5.4	-8.6
अंतर	-2,388.0	-4,040.0

* अंतर पिछले सप्ताह से, स्रोत- आईबीजेए, संकलन- बीएस रिसर्च

बाजार के विश्लेषकों ने कहा कि कीमती धातुओं में यह गिरावट आज भी इसलिए जारी रही क्योंकि ताजी खरीद नहीं हो रही है। इसका कारण यह है कि इस पीली धातु के दाम अब भी काफी ज्यादा हैं, जबकि खुदरा मांग नदारद है।

कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष और कारोबार प्रमुख (वैश्विक कारोबार बैंकिंग और कीमती धातु) शेखर भंडारी ने कहा कि कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी और तेल के दामों में गिरावट से शेयर बाजार में मंदी का रुख है और सोने का भाव सात साल के शीर्ष स्तर पर चल रहा है। सोने की मांग काफी कम है जो देश भर की 'ऐच्छिक मांग' के अनुरूप है। सोने के दामों में अधिकता के साथ-साथ अस्थिरता ने खरीदारों को दूर रखा हुआ है।

हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि जब बाजार संभलेगा तो मांग में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि अगर चिंता में कमी आती है तो अगले महीने मांग में सुधार हो सकता है। जब दामों में स्थिरता आएगी या दाम कम होंगे तो सोना खरीदने का इंतजार करने वाले लोग खरीद कर सकते हैं।

फिलहाल असलियत यह है कि सोने की मांग तकरीबन खत्म हो चुकी है। यह बात आयात की लागत और बाजार मूल्य में भी नजर आई है। सोने का बंद भाव 41,849 प्रति 10 ग्राम है जो आयात की लागत से अब भी 400 रुपये कम है और कारोबार के दौरान दी जा रही छूट प्रति 10 ग्राम तकरीबन 900 से 1,000 रुपये के बीच रही। दामों में बहुत अधिकता और अस्थिरता की वजह से पिछले कुछ दिनों से आयात में भी खासी गिरावट आई है।

फरवरी में वनस्पति तेल आयात 10.5 प्रतिशत घटा

खाद्य तेल उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, रिफाइंड पाम तेल के आयात में कमी के कारण पिछले महीने वनस्पति तेल का आयात 10.5 प्रतिशत घटकर 11.12 लाख टन रह गया। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने एक बयान में कहा कि फरवरी 2020 के दौरान वनस्पति तेल का आयात 11,12,478 टन का हुआ था, जो फरवरी 2019 में 12,42,533 टन था। एसईए ने कहा कि पिछले महीने के कुल वनस्पति तेल आयात में से 10,89,661 टन खाद्य तेल था, जबकि 22,817 टन गैर-खाद्य तेल था।

नवंबर 2019 से फरवरी 2020 के दौरान वनस्पति तेल का समग्र आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 48,62,849 टन की तुलना में 6.1 प्रतिशत घटकर 45,63,791 टन रह गया। तेल वर्ष नवंबर से लेकर अगले वर्ष अक्टूबर माह तक का होता है। एसईए ने कहा कि आठ जनवरी, 2020 से आरबीडी पामोलिन को प्रतिबंधित सूची में रखे जाने के कारण फरवरी 2020 में इसका आयात भारी कमी के साथ मात्र 33,677 टन रह गया।

उन्होंने कहा कि कच्चे सूरजमुखी और कच्चे सोयाबीन तेल के आयात में तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि पाम तेल और हल्के तेलों के बीच का मूल्य अंतर लगभग 75 से 80 डॉलर प्रति टन तक कम हो गया। इससे हल्के माने जाने तेलों का आयात बढ़ गया। *भाषा*

कोरोना के डर से घटी सोयाखली की मांग

अफवाहों के कारण चिकन की बिक्री घटी

भाषा
इंदौर, 13 मार्च

कोरोनावायरस के डर से मुंबई के माहिम में चिकन के दाम 120 रुपये किलो से गिरकर 40 से 50 रुपये तक पहुंच गए

भारी मूल्य प्रतिस्पर्धा के चलते देश के सोयाखली उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले ही मुश्किलों से जूझना पड़ रहा था। अब कोरोनावायरस के प्रकोप ने घरेलू मोर्चे पर भी उनके लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं, क्योंकि इस बीमारी को लेकर फैल रही अफवाहों के कारण पोल्ट्री उद्योग से सोयाखली की मांग गिर गई है।

> एफएसएसएआई ने कहा है कि पशुओं से मनुष्यों में कोरोनावायरस के फैलने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है

सोया खली वह उत्पाद है जो प्रसंस्करण इकाइयों में सोयाबीन का तेल निकाल लेने के बाद बचा रह जाता है। यह उत्पाद प्रोटीन का बड़ा स्रोत है। दुनिया के कई देशों में इससे मुर्गियों का दाना तैयार किया जाता है। इंदौर स्थित सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक ने कहा, 'कोरोनावायरस के वैश्विक संकट के कारण सोया खली की मांग में बड़ी कमी देखी जा रही है।' उन्होंने मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा, 'फिलहाल कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कोरोनावायरस का यह संकट कब दूर होगा।'

इस बीच, कोरोनावायरस को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है और लोगों से मांसाहार छोड़कर शाकाहार अपनाने की अपील की जा रही है। कारोबारी सूत्रों के मुताबिक इन अफवाहों से देश भर में पोल्ट्री उद्योग को बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि लोगों ने डर के कारण चिकन और अंडे खाना कम कर दिया है।

बहरहाल, सरकार इस सिलसिले में लोगों को पहले ही सचेत कर चुकी है। केंद्रीय मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने पिछले हफ्ते कहा था कि लोग उन अफवाहों पर ध्यान न दें जिनमें कहा जा रहा है कि कोरोनावायरस अंडे, चिकन, मटन और समुद्री भोजन जैसे मांसाहारी खाद्य पदार्थों के जरिये फैलता है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) के साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने भी कहा है कि पशुओं से मनुष्यों में कोरोनावायरस के फैलने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

यात्रा रद्द तो शुल्क माफ हो

अनीश फडणीस

फोटोः दलीप कुमार

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रतीक्षा करते यात्री

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने वैश्विक विमानन कंपनियों से कहा है कि वे टिकट रद्द कराने पर शुल्क माफ करने के बारे में विचार करें। डीजीसीए ने कहा है कि उन यात्रियों को राहत मुहैया कराई जाएगी, जिनकी यात्रा योजना में कोरोनावायरस की वजह से व्यवधान पैदा हुआ है। विमानन नियामक ने शुक्रवार को यह सुझाव दिया। सरकारी आदेशों के कारण ग्राहकों को अपनी यात्रा रद्द करने को बाध्य होना पड़ रहा है, लेकिन किराये के नियमों के कारण उन्हें टिकट की पूरी राशि वापस नहीं मिल पा रही है।

वैश्विक स्तर पर विमानन कंपनियां ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के तारीख या गंतव्य स्थल में बदलाव करने की पेशकश कर रही हैं, लेकिन टिकट की राशि किराये के नियमों के आधार पर ही वापस लौटाई जा रही है। विमानन कंपनियां किराये के प्रकार के आधार पर टिकट रद्द करने का शुल्क काटती हैं। इस वजह से सोशल मीडिया पर विमानन कंपनियों के खिलाफ बड़ी तादाद में शिकायतें आ रही हैं।

डीजीसीए के उप महानिदेशक सुनील कुमार ने भारत से परिचालित सभी विदेशी विमानन कंपनियों को भेजे परिपत्र में कहा, 'रोजाना उड़ानें कम या रद्द की जा रही हैं। इससे यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौजूदा माहौल में अगर विमानन कंपनियां यात्रा रद्द करने या तारीख में बदलाव के शुल्कों को माफ कर या अन्य प्रोत्साहन मुहैया कराकर इस मुश्किल घड़ी में अपने यात्रियों का समर्थन करेंगी तो यह बहुत अच्छा होगा। यात्रियों की दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए विमानन कंपनियां विचार-विमर्श और उचित फैसला लें सकती हैं।' एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों को अलग से यात्रियों को राहत देने की सलाह दी गई है।

मार्च 14 -16 से भारत की अपनी उड़ानें स्थगित करने वाली लुफ्थांसा और स्विस ने अपनी छूट अवधि बढ़ा दी है। इन विमानन कंपनियों ने कहा कि ग्राहक नई उड़ान की बुकिंग के बिना भी उनका टिकट वैध रहेगा। वे इस टिकट को बाद में इस्तेमाल कर सकेंगे। नई यात्रा 31 दिसंबर तक पूरी की जा सकती है। सिंगापुर की सस्ती विमानन कंपनी स्कूट ट्रैवल वाउचर के रूप में रिफंड की पेशकश कर रही है। ग्राहक इन वाउचर को आगे की उड़ानों में रीडीम करा सकेंगे।

हवाईअड्डा: भरपाई की मांग

अरिदम मजूमदार

देश में हवाईअड्डे से जुड़े निजी परिचालकों ने विमानन कंपनियों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के लिए सरकार से इजाजत मांगते हुए कहा है कि यात्रियों और विमाननों की आवाजाही में कमी से घाटा हो रहा है। नागरिक विमानन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला से निजी परिचालकों के एक संगठन ने कहा, 'विमानों और यात्रियों की कमी की वजह से हवाईअड्डे की कमाई पर काफी असर पड़ा है। इस गंभीर समस्या और हवाईअड्डा परिचालकों पर बन रहे दबाव की स्थिति को देखते हुए मामूली सुविधा शुल्क लगाने की मांग की जा रही है जो विमान किराये का ही हिस्सा होगा ताकि बढ़े हुए परिचालन लागत को कवर किया जा सके।' निजी हवाईअड्डा परिचालक आमतौर पर विमानन कंपनियों पर उपयोगकर्ता विकास फीस, यात्री सेवा फीस और विकास फीस के नाम पर शुल्क वसूलते हैं।

बुधवार को सरकार ने घोषणा की थी कि 15 अप्रैल तक के लिए सभी मौजूदा वीजा को रद्द किया जा रहा है ताकि कोरोनावायरस पर नियंत्रण किया जा सके जो तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे एक वैश्विक महामारी के तौर पर वर्गीकृत किया है। इस कदम की वजह से बड़ी तादाद में लोगों को पर्यटन की योजना रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि विमानन कंपनियों ने भी विमान सेवाओं में कटौती कर दी। फरवरी से ही भारत में संचालन करने वाली विदेशी विमान कंपनियों ने मार्च के अंत तक करीब 492 उड़ानों को रद्द कर दिया। भारतीय विमानन कंपनियों ने 96 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कैंसिल कर दी। बुधवार के आदेश के बाद इसमें बढ़ोतरी के पूरे आसार हैं।

एक हवाईअड्डे के प्रवक्ता ने कहा, 'फरवरी में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी सामान्य स्तर के मुकाबले 20 फीसदी की कमी जबकि मार्च में लगभग 50 फीसदी की कमी देखी जा रही है। सामान्यतौर पर हवाईअड्डे पर रोजाना 14,000 से 15,000 तक अंतरराष्ट्रीय यात्री आते हैं लेकिन अब इनकी तादाद घटकर रोजाना 6,000 से 7,000 हो गई है।'

निजी हवाईअड्डे के अधिकारियों का कहना है कि सरकार के साथ राजस्व साझेदारी व्यवस्था की वजह से उन पर काफी दबाव की स्थिति है। निजीकरण के दौरान सरकार के साथ हुए समझौते के मुताबिक देश के दो बड़े हवाईअड्डे जीएमआर समूह का दिल्ली हवाईअड्डा और जीवीके समूह का मुंबई हवाईअड्डा अपनी सालाना कमाई के 46 और 38.7 फीसदी हिस्से का भुगतान सरकार के स्वामित्व वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को करता है। निजी हवाईअड्डा परिचालकों के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के पास जमा की गई लक्षित कारोबारी योजना के हिसाब से एक तिमाही का अग्रिम भुगतान करना होता है। उनका कहना है, 'हमने लक्षित योजना के हिसाब से वित्त वर्ष 2021 के लिए हमने सरकार को साल की शुरुआत में ही भुगतान कर दिया है। लेकिन अचानक हालात में बदलाव दिखने लगा।'

विदेशी विमानन कंपनियों ने भारत की उड़ानें कीं रद्द

विमानन कंपनियां	रद्द उड़ानों की संख्या
एयर चाइना	17
चाइना इस्टर्न एयरलाइंस	56
सिंगापुर एयरलाइंस	36
सिल्क एयर	67
एयर एशिया	16

कोरोना के देश में बढ़ रहे मामले

कई राज्यों ने स्कूल कॉलेज किए बंद। देश भर में अब तक संक्रमण के 81 मामलों की पुष्टि

देश में कोरोनावायरस संक्रमण के 81 मामलों की पुष्टि हुई है जिनमें इटली के 16 नागरिक शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पूरे देश में 42 हजार लोगों को सामुदायिक निगरानी में रखा गया है। अधिकारी ने कहा कि कोरोनावायरस स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि भारत ने अब तक मालदीव, अमेरिका, मेडागास्कर और चीन सहित विभिन्न देशों से 1,031 लोगों को निकाला है। अधिकारियों ने बताया कि ईरान में फंसे बाकी भारतीयों को वापस लाने की कवायद शनिवार को शुरू होगी। एअर इंडिया इटली के मिलान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भी शनिवार को विमान भेजेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को बताया कि 44 भारतीय जायरीनों का दूसरा दल कोरोनावायरस प्रभावित ईरान से स्वदेश लौट आया है। इस बीच उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अधिसूचना में कहा कि अदालत का कामकाज सिर्फ आवश्यक मुकदमों तक सीमित रहेगा। मुकदमे से संबंधित अधिवक्ताओं के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को न्यायालय कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

नई दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर संक्रमण से बचाव के लिए सफाई करते कर्मी (पीटीआई)

- प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षेस नेताओं से संयुक्त रणनीति बनाने का रखा प्रस्ताव
- ओडिशा में सरकार ने वायरस से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपये किए आवंटित
- देश में केवल 19 अंतरराष्ट्रीय सीमा चौकियों से ही आवाजाही हो सकेगी

संयुक्त रणनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस से निपटने के लिए दक्षेस देशों द्वारा एक संयुक्त रणनीति बनाने का प्रस्ताव शुक्रवार को दिया जिसका नेपाल और श्रीलंका जैसे सदस्य देशों ने स्वागत किया है। मोदी ने दुनिया के सामने मिसाल पेश करने के मकसद से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के नेताओं के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये चर्चा कर शुक्रवार को प्रस्ताव दिया ताकि कोरोनावायरस से लड़ने के लिए मजबूत रणनीति बनाई जा सके।

आईपीएल टला

इस बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही एकदिवसीय शृंखला के बाकी दो मैच रद्द कर दिए गए हैं। वहीं बीसीसीआई ने शुक्रवार को कोविड-19 महामारी की वजह से 29 मार्च से शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को 15 अप्रैल तक निलंबित कर दिया।

उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल-कॉलेजों को 22 मार्च तक बंद कर देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने महामारी रोग अधिनियम लागू कर दिया है। केरल विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार ने परीक्षा करा रहे संस्थानों को छोड़कर राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 31 मार्च तक बंद करने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए वायरस को आपदा घोषित किया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया। बिहार में भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, चिड़ियाघर और पार्क 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है। मध्यप्रदेश के स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया।

सीमा पर नियंत्रण

संक्रमण को देखते हुए अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने कुल 37 अंतरराष्ट्रीय सीमा चौकियों में से केवल 19 पर आवाजाही जारी रखने का फैसला किया है और भारत-बांग्लादेश के बीच ट्रेन और बसों का परिचालन 15 अप्रैल तक या उससे पहले तक इस संबंध में लिए गए फैसले के अनुरूप स्थगित रखने का फैसला किया है। *एजेंसियां*

शिक्षा संस्थानों में तालाबंदी

कोरोनावायरस के चलते देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों, आईआईटी, आईआईएम समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों ने कक्षाओं को बंद करने के साथ ही दीक्षांत समारोह को टाल दिया है। आईआईएम अहमदाबाद ने 21 मार्च को होने जा रहे दीक्षांत समारोह जबकि आईआईएम बेंगलूरु ने 20 मार्च को होने वाले दीक्षांत समारोह को टाल दिया है। दूसरी ओर, आईआईटी दिल्ली ने 31 मार्च तक सभी कक्षाओं तथा परीक्षाओं को रोक दिया है और इस अवधि में छात्रों तथा अध्यापकों को किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन कराने के लिए परहेज करने के लिए कहा है। आईआईएम इंदौर 24-25 मार्च को दीक्षांत समारोह आयोजित करा रहा था जिसे रद्द कर दिया गया है। आईआईटी दिल्ली ने कक्षाएं तथा परीक्षाएं टालने के साथ ही विदेश भ्रमण को लेकर भी छात्रों को चेतावनी दी है। एजुकेशन-तकनीक क्षेत्र की कंपनियां छात्रों तथा संस्थानों को मदद दे रही हैं। ऑनलाइन एजुकेशन मंच कोर्सेरा वायरस से प्रभावित संस्थानों को कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रम मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। *बीएस*

कर्मचारियों के लिए सतर्क हुईं कंपनियां

पृष्ठ-1 का शेष

गूगल का कार्यालय आरएमजेड इनफिनिटी में है। इस टेक पार्क में आज कोई चहलपहल देखने को नहीं मिली क्योंकि यहां काम करने वाले 10 हजार कर्मचारियों में से अधिकांश ने घर से ही काम करना मुनासिब समझा। आरएमजेड कॉर्प ने कहा कि परिसर में स्थित सभी कंपनियों को स्थिति की जानकारी दे दी गई है और दवा छिड़काव तथा साफ-सफाई के सारे उपाय किए गए हैं। ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एमेजॉन ने भी अपने सभी कर्मचारियों को परामर्श जारी कर इस महीने के अंत तक घर से काम करने को कहा है। भारत में एमेजॉन के प्रमुख अमित अग्रवाल ने कर्मचारियों से कहा कि एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया जा रहा है। दुनियाभर में एमेजॉन के तीन कर्मचारियों में कोरोनावायरस की पुष्टि हुई है। इनमें एक मामला अमेरिका के सिएटल में और दो इटली में सामने आए हैं। कंपनी पहले की घोषणा कर चुकी है कि कोविड-19 से संक्रमित या अलग रखे गए उसके कर्मचारियों को दो सप्ताह तक का वेतन मिलेगा। कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में लिखा कि काम से दूर रहने के बावजूद इस अतिरिक्त भुगतान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी वेतन की चिंता किए बगैर स्वस्थ होकर काम पर लौटें। उबर इंडिया के अधिकांश कर्मचारी पिछले एक सप्ताह से घर से ही काम कर रहे हैं और कंपनी ने एक परामर्श जारी कर उन्हें 6 अप्रैल तक ऐसा करने को कहा है। माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों के पास कोरोनावायरस के संक्रमण से पहले ही घर से काम करने का विकल्प मौजूद है और अधिकांश कर्मचारी अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह फेसबुक में भी अधिकांश कर्मचारियों के पास घर से काम करने का विकल्प है। सूत्रों के मुताबिक शॉर्ट वीडियो मैसेसिंग ऐप टिकटॉक की मूल कंपनी बाईटेंडेंस ने भी अपने सभी कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प दिया है। फ्लिपकार्ट ने भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बेंगलूरु के बेलंदूर कार्यालय में काम करने वाले 10 हजार कर्मचारियों को तीन दिन के लिए घर से काम करने को कहा है। वॉलमार्ट के मालिकाना हक वाली इस कंपनी ने कॉरपोरेट मुख्यालय से काम करने वाले कर्मचारियों को बुधवार से तीन दिन के लिए घर से काम करना अनिवार्य कर दिया है।

कई ई-कॉमर्स कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने का दिया विकल्प

ब्रोकरेज स्टार्ट अप कंपनी जीरोधा ने भी अपने सभी 1,200 कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। स्विगी, ओला, बाएजू और उड़ान जैसी कई अन्य कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। कंपनियों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उपाय तेज कर दिए हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान-बेंगलूरु ने भी 20 मार्च को होने वाले वार्षिक दीक्षांत समारोह स्थगित कर दिया है।

इस बीच सरकार ने शुक्रवार को एन95 समेत अन्य मास्क और सैनेटाइजर को जून तक अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में लाने की घोषणा की। कोरोना वायरस के फैलने के साथ इन दोनों उत्पादों की कमी और कालाबाजारी के कारण यह कदम उठाया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार ए उत्पाद अनिवार्य वस्तु श्रेणी में जून तक रहेंगे। इस कदम का मकसद लोगों मास्क और सैनेटाइजर के वाजिब मूल्य पर उपलब्ध कराना और जमाखोरी तथा कालाबाजारी पर रोक लगाना है।

वैश्विक बाजार में कोरोना से बढ़ी हलचल

दुनिया भर की राजनीति, खेल और फिल्मी दुनिया की कई मशहूर हस्तियां भी आईं कोरोनावायरस संक्रमण की चपेट में

कोरोनावायरस का संकट गहराने के साथ ही वैश्विक शेयर बाजारों में शुक्रवार को भारी हलचल दिखी और दुनिया के सभी क्षेत्रों के लोग इससे प्रभावित दिखे चाहे वह राजनीति, खेल जगत या सिनेमा की दुनिया के सितारे हों। यूरोप में संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है लेकिन ईरान में शुक्रवार को ज्यादा लोगों की मौत हुई जबकि पूर्वी अफ्रीका के देशों केन्या और इथियोपिया में पहला मामला दर्ज किया गया। फिलहाल 18 अफ्रीकी देशों में कोरोनावायरस फैल चुका है। दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में खौफ का साया मंडरा रहा है कि इस महामारी से दुनिया में मंदी न छा जाए जबकि कई देशों के केंद्रीय बैंक आपातकालीन स्थिति के लिए उपाय कर रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था को उबारा जा सके।

वहीं यूरोपीय देशों में पोलैंड में कोरोनावायरस से पहली मौत हुई है जहां 47 लोग संक्रमित हैं। इटली में मरने वालों की तादाद 1,000 से अधिक हो गई है जबकि 15,113 संक्रमित हैं। ब्रिटेन में संक्रमण के 590 मामले की पुष्टि हो चुकी है। फ्रांस में सोमवार से सभी स्कूल और विश्वविद्यालय बंद हो जाएंगे जहां 61 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य न्यू साउथ वेल्स है जहां 70 लाख से ज्यादा आबादी है और यहां के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी केरी चैंट कहते हैं कि राज्य की 5 फीसदी की आबादी यानी करीब 350,000 लोगों को वायरस की वजह से अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत पड़ी। गुरुवार को हॉलीवुड सितारे टॉम हैंक्स ने भी ऑस्ट्रेलिया में घोषणा की थी कि वह और उनकी पत्नी अभिनेत्री रीटा विल्सन कोरोनावायरस से संक्रमित हैं। टूडो ने कहा कि वह दो हफ्ते तक अलग रहेंगे क्योंकि उनकी पत्नी में असहज लक्षण दिख रहे थे। कनाडा में वायरस संक्रमण के 145 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से खेल से जुड़े कई कार्यक्रमों पर भी असर पड़ा है और प्लेयर्स चैंपियनशिप तथा ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला वन ग्रां प्री को भी टाल दिया गया है।

कई देशों के केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए कर रहे उपाय

जकार्ता में सुरक्षा के लिए मास्क पहने स्वास्थ्य कर्मी

मृतकों की तादाद बढ़ी

दुनिया की कई मशहूर हस्तियां कोरोनावायरस संक्रमण से जूझ रही हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पत्नी, ऑस्ट्रेलिया के गृहमंत्री और चेल्सी फुटबॉल क्लब के एक खिलाड़ी भी संक्रमण की चपेट में हैं। दुनिया के 121 देशों में करीब 135,000 लोग संक्रमित हैं जबकि 5,043 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में अब तक3,176 लोगों वहीं इटली में 1,016 और ईरान में 514 लोगों की मौत हुई है। ईरान में 24 घंटे के भीतर सेना के जरिये सड़कें खाली कराने की योजना है। कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे के कारण दुनियाभर में ठप पड़ रही आर्थिक गतिविधियों के बीच हॉलीवुड पर भी बुरा असर पड़ा है। यूरोपीय देशों में पोलैंड में कोरोनावायरस से पहली मौत हुई है जहां 47 लोग संक्रमित हैं। इटली में मरने वालों की तादाद 1,000 से अधिक हो गई है जबकि 15,113 संक्रमित हैं। ब्रिटेन में संक्रमण के 590 मामले की पुष्टि हुई है। फ्रांस में सोमवार से सभी स्कूल और विश्वविद्यालय बंद हो जाएंगे जहां 61 लोगों की मौत हो चुकी है

राहत उपाय

कोरोनावायरस के आर्थिक असर से निपटने के लिए शुक्रवार को कई देशों की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने आपात स्थिति के लिए कई उपायों पर जोर दिया ताकि गिरावट से जूझ रहे वित्तीय बाजार को थोड़ी राहत मिले जबकि कई बड़े आयोजन रद्द कर दिए गए। अमेरिकी सांसद और व्हाइट हाउस के बीच कोरोनावायरस के लिए आर्थिक राहत पैकेज को लेकर सहमति बन गई है जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी।

बाजार पर असर

शुक्रवार को संक्रमण के मुख्य केंद्र रहे चीन के वुहान में केवल पांच नए मामले सामने आए। चीन से सकारात्मक खबर मिलने के बावजूद वैश्विक बाजार में निराशा है। वर्ष 1987 के बाद गुरुवार को वॉल स्ट्रीट के लिए बेहद खराब दिन रहा और इसके शेयरों में 10 फीसदी की गिरावट देखी गई जिसके असर से जापान के निक्केई में भी 6 फीसदी तक की गिरावट देखी गई। एशियाई बाजारों में भी ऐसा ही रुझान जारी रहा। हालांकि अमेरिका के राहत पैकेज की उम्मीद में यूरोपीय शेयरों और तेल की कीमतों में सुधार दिखा। *एजेंसियां*